खण्ड-07 सत्र-05 / अंक-53

सोमवार 19 फरवरी, 2024 / 30 माघ, 1945 (शक)

दिल्ली विधान सभा

की

कार्यवाही

सत्यमेव जयते

सातवीं विधान सभा

पाँचवां सत्र

अधिकृत विवरण

(खण्ड-07 सत्र-05 में अंक 50 से अंक 70 तक सम्मिलित हैं)

दिल्ली विधान सभा सचिवालय

पुराना सचिवालय, दिल्ली-110054

सम्पादक वर्ग

EDITORIAL BOARD

राज कुमार

सचिव

RAJ KUMAR

Secretary

महेन्द्र गुप्ता

उप-सचिव (सम्पादन)

MAHENDRA GUPTA

Deputy Secretary (Editing)

विषय सूची

सत्र-4 सोमवार, 19 फरवरी, 2024/30 माघ, 1945 (शक) अंक-53

क्र.सं.	विषय	पृष्ठ सं.
1.	सदन में उपस्थित सदस्यों की सूची	1-2
2.	विशेष उल्लेख (नियम-280)	3-30
3.	सदन पटल पर प्रस्तुत कागज़ात	31
4.	ध्यानाकर्षण (नियम-54)	32-77

दिल्ली विधान सभा

की

कार्यवाही

सत्र-5 सोमवार, 19 फरवरी, 2024/30 माघ, 1945 (शक) अंक-53

दिल्ली विधान सभा

निम्नलिखित सदस्य सदन में उपस्थित हुए:

1. श्री अजेश यादव
2. श्री अखिलेशपति त्रिपाठी
3. श्रीमती ए. धनवंती चंदीला ए.
4. श्री अब्दुल रहमान
5. श्रीमती भावना गौड
6. श्री बी एस जून
7. श्री दिनेश मोहनिया
8. श्री हाजी युनूस
9. श्री जय भगवान
10. श्री जरनैल सिंह
11. श्री करतार सिंह तंवर
12. श्री कुलदीप कुमार
13. श्री महेंद्र गोयल
14. श्री मुकेश अहलावत
15. श्री नरेश यादव
16. श्रीमती प्रीति जितेंद्र तोमर
17. श्री प्रवीण कुमार
18. श्रीमती प्रमिला धीरज टोकस
19. श्री राजेश गुप्ता
20. श्री राजेन्द्र पाल गौतम

21. श्रीमती राजकुमारी ढिल्लों
22. श्री रोहित कुमार
23. श्री शरद कुमार चौहान
24. श्री सोमदत्त
25. श्री शिवचरण गोयल
26. श्री सोमनाथ भारती
27. श्री सही राम
28. श्री एस. के. बग्गा
29. श्री वीरेंद्र सिंह कादियान
30. श्री अजय दत्त
31. श्री मदन लाल
32. श्री प्रलाद सिंह साहनी
33. श्री प्रकाश जारवाल
34. श्री ऋतुराज गोविंद
35. श्री राजेश ऋषि
36. श्री संजीव झा
37. श्री सुरेंद्र कुमार
38. श्री विशेष रवि

दिल्ली विधान सभा

की

कार्यवाही

सत्र-5 सोमवार, 19 फरवरी, 2024/30 माघ, 1945 (शक) अंक-53

दिल्ली विधान सभा

सदन पूर्वाह्न 11.20 बजे समवेत हुआ ।

माननीय अध्यक्ष (श्री राम निवास गोयल) पीठासीन हुए ।

माननीय अध्यक्षः मैं माननीय सदस्यों से प्रार्थना कर रहा हूं कि 15 मिनट घंटी बजती रही है ये बहुत बड़ी लापरवाही है कृपया इसको दुरूस्त करें, धन्यवाद। 280 श्री जय भगवान जी, (अनुपस्थित)। श्री भूपेन्द्र सिंह जून जी।

विशेष उल्लेख (नियम-280)

श्री बी.एस. जूनः धन्यवाद अध्यक्ष जी, अध्यक्ष जी बिजवासन विधानसभा में पांच वार्ड्स हैं और उन पांच वार्ड्स में इलीगल कॉलोनिज़ हैं अनॉथराइज कॉलोनिज 35 गांव पड़ते हैं 13 और जे. जे. कलस्टर्स पड़ते हैं 14, डीडीए की पॉकेट्स हैं वो 5 हैं और सोसायटिज ग्रुप हाउसिंग की 19 हैं, सर इतने वास्ट एरिया में इतनी पोपुलेशन में मोहल्ला क्लीनिक हैं सिर्फ 2 और उन दो मैं से भी एक नॉन फंग्शनल है क्योंकि वो रेन्टिड एकॉमडेशन में चल रहा था लैंड लॉर्ड ने जो है

कोर्ट को एप्रोच किया, कोर्ट के आदेश पर वो उनको एविक्ट करना पड़ा और वो जो है मोहल्ला क्लीनिक डंप हो गया। तो सही मायने में आज एक मोहल्ला क्लीनिक काम कर रहा है। एक मोहल्ला क्लीनिक कापासहेड़ा में कोरोना से पहले बनकर तैयार हो गया लेकिन वो आज तक स्टार्ट नहीं हुआ, कई बार मैंने चिट्ठियां भी लिखीं। हैल्थ डिपार्टमेंट पता नहीं क्यों उस मोहल्ला क्लीनिक कॉन्सेप्ट को फेल करने पर तुला हुआ है। मंत्री जी से पर्सनली भी रिक्वेस्ट की, लैटर भी लिखे उन्होंने लैटर्स को मार्क कर दिया सेक्रेटरी हैल्थ को, सेक्रटरी हैल्थ जो है उनको डंप कर देते हैं। तो सर इतनी बड़ी पोपुलेशन में और एक मोहल्ला क्लीनिक आज फंक्शनल है और मोहल्ला क्लीनिक गरीब आदमियों के लिये एक आशा की किरण है, फ्री ट्रीटमेंट मिलता है, फ्री टैस्टिंग हो रही है, फ्री जो है मैडिसन्स मिलती हैं। इतने एरिया में एक मोहल्ला क्लीनिक क्या करेगा? कई बार साइट दिखाई उस पर गोल-गोल जवाब आ जाता है कि feasibility नहीं है, feasibility नहीं है। इसका कोई रिज़न तो होगा, सर, बतायें तो सही कि feasibility क्यों नहीं है। अगर स्पेस सुटेबल नहीं है, हम दूसरा स्पेस देंगे। पीडब्ल्यूडी की लैंड पड़ी है, जल बोर्ड की लैंड पड़ी है लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई इस मामले में नहीं हुई। तो मेरी आपके माध्यम से मंत्रीजी से रिक्वेस्ट है कि वो पर्सनल इन्ट्रस्ट लें और इनकेये जो हैल्थ डिपार्टमेंट के लोग हैं इनको pull up करें कि भई एक मोहल्ला क्लीनिक में पूरी constituency में काम कैसे चलेगा। ऐसा लगता है सर हैल्थ डिपार्टमेंट के ऑफिशियल्स मोहल्ला क्लीनिक कन्सेप्ट को बर्बाद करने पर तुले हुये हैं। तो मेरी यही प्रार्थना है कि इस पर इमिडेट्ली गौर किया जाये और ज्यादा से ज्यादा

मोहल्ला क्लीनिक बिजवासन विधानसभा में एस्टिैब्लिश किये जायें, थैंक्यू सर।

माननीय अध्यक्षः श्री विशेष रवि जी।

श्री विशेष रविः धन्यवाद सर, सर मैं दिल्ली के जो बुजुर्ग हैं उसमें उनको जो पेंशन से संबंधित दिक्कत आ रही है उसको आपके समक्ष चाहता हूं रखना। सर दिल्ली के अंदर जो पेंशन सिस्टम है अगर हम ओल्ड एज़ पेंशन की बात करें तो उसमें एक शेयर है जो दिल्ली गर्वमेंट को पे करना होता है और उसमें एक छोटा सा शेयर है जो सैन्ट्रल गर्वमेंट से आता है। ये पिछले कुछ महीनों से या अब तो साल लगभग होने वाला है कि हर महीने जो सैन्ट्रल गर्वमेंट से शेयर आता है पेंशन का वो समय से नहीं आता है और इतना लेट हो जाता है कि जो बुजुर्ग हैं वो अपनी पेंशन की जो है वो बाट देखते रहते हैं, परेशान होते रहते हैं, वो हमारे ऑफिस में चक्कर काटते रहते हैं लेकिन हमारे पास उनको कोई जवाब जो है देने के लिये नहीं होता है। अगर आप इस महीने की बात करें तो इस महीने भी दिल्ली के अंदर किसी भी डिस्ट्रिक के अंदर सैन्टर का जो शेयर है सर उसमें जो ज्यादातर जो बुजुर्ग हैं वो 70 प्लस वाले लोग हैं। आज भी इस महीने भी दिल्ली की किसी भी डिस्ट्रिक के अंदर 70 प्लस के जो बुजुर्ग हैं उनकी पेंशन नहीं आई है। आज 19 तारीख हो गई है पेंशन का समय जो है वो 5 से 10 तारीख के बीच में होता है। हम सब जानते हैं कि जितने बुजुर्ग हैं जो खासतौर पर जो है वो ज्यादा जो बुजुर्ग हैं वो पूरी तरह जो हैं वो पेंशन पर आने वाली जो अमांउट है उसी पर जो है वो

अपना जीवन यापन करते हैं चाहे दवाई लेनी हो, चाहे कहीं जाना हो, कहीं कुछ और काम करना हो, सब कुछ उनका पेंशन पर आधारित होता है लेकिन सैन्ट्रल गर्वमेंट जो है वो पिछले कुछ महीनों से लगातार जो है, जैसा मैंने कहा कि हर महीने का ये हो गया है कि पेंशन को जो है वो रिलीज़ नहीं करते हैं। दिल्ली गर्वमेंट परस्यु करती रहती है, समाज कल्याण विभाग जो है चिट्ठियां लिखता रहता है,बात करता रहता है लेकिन वो जो है समय से पेंशन रिलीज नहीं करते और जब करते हैं तो इतना लेट हो जाता है कि बुजुर्ग जो है वो हमारे कार्यालयों के अंदर चक्कर काट-काटकर परेशान हो जाते हैं। तो मेरी आपके माध्यम से ये प्रार्थना है कि सैन्ट्रल गर्वमेंट जो है वो अपना जो काम है, अपना जो धर्म है जो बुजुर्ग जिनको पेंशन देनी है उसको जो है ठीक से निभायें और पेंशन जो है हर महीने जारी करने की कृपा करें, धन्यवाद।

माननीय अध्यक्षः श्री मदन लाल जी।

श्री मदन लालः धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे अपने क्षेत्र की समस्या के बारे में मौका दिया। अध्यक्ष महोदय, दिल्ली सरकार की नीति कि हर घर को 200 यूनिट फ्री बिजली मिले, को अब derail करने के लिये, या मैं कहूं इस सुविधा का लाभ लोगों को ना मिले इसके लिये अब एक नया कानून बनाना शुरू कर दिया है। जब भी कोई नया कनैक्शन अप्लाई करता है तो अब बीएसईएस के अधिकारी उससे उस पर्टिकुलर जगह की या तो सेल डीड की कॉपी मांगने लगे हैं और साथ के साथ वहां का आधार कार्ड मांगने लगे हैं। गांव की प्रोपर्टी जो पहले ग्राउंड फ्लोर पर थी, फिर फर्स्ट फ्लोर बनी, सैकेंड

फ्लोर बनी अब उनकी अलग-अलग stage sale deed तो हो नहीं सकती, एक प्लॉट की सेल डीड हो गई। जहां कहीं और कॉलोनिज़ हैं उनका भी सेम स्टेट्स है। जिस समय सेल डीड हुई उस समय उस मकान का स्टेट्स शायद एक फ्लोर का था या दो फ्लोर का रहा होगा पर वो तीन फ्लोर का चार फ्लोर का तो नहीं हुआ हालांकि सरकार ने परमीशन दे रखी है। ऐसे में अगर बिजली का किसी को नया कनैक्शन चाहिये तो बिजली के अधिकारी जान-बूझकर तंग करने के लिये कि उनको सुविधा का लाभ ना मिले या चोर दरवाजे से मिले क्योंकि आदमी जब दुःखी होगा तो चोर दरवाजा ढूंढेगा। तो बीएसईएस के अधिकारियों ने अपनी मर्जी से अब एक नया कानून बनाना शुरू कर दिया है जिसका कोई औचित्य नहीं है। वो कहते हैं कि अगर आपको फर्स्ट फ्लोर पर बिजली चाहिये, सैकेंड फ्लोर पर बिजली चाहिये, थर्ड फ्लोर पर चाहिये तो आपको सेल डीड की कॉपी दिखानी पड़ेगी। अब ये बड़ी असमंजस की स्थिति है। तो मैं माननीय मंत्री महोदय को आपके माध्यम से इस बारे में रिक्वेस्ट करूंगा कि उसका संज्ञान लें और बिजली के अधिकारियों को डायरेक्शंस इश्यू करें कि इस तरह लोगों को तंग ना करें क्योंकि अगर हमने जांच-पड़ताल करवाई जो हम नहीं करा सकते, मंत्री महोदय करा सकते हैं तो पता चलेगा कि बहुत सारी जगह तो बिजली लग रही है पर जहां लोग पैसा नहीं दे रहे हैं वहां लोगों को अनाप-शनाप तरीके से तंग किया जा रहा है। तो आपके माध्यम से, मंत्री जी मान गये हैं, मुझे लगता है समस्या का समाधान होगा और लोगों को, हमारी नज़र में तो हमारे तीन माननीय

मंत्री बैठे हैं हमारी बात ऊपर तक पहुंच जायेगी।.. अध्यक्ष महोदय ये समस्या मुझे लगता है और कई जगह आ रही होगी, लोगों को नहीं पता चलता है कई बार। लोग आते हैं हमसे बात करते हैं और कई बार तो ऐसा हुआ है कि चलती-चलती बिल्डिंग जो बिल्डिंग तैयार ही नहीं हुई है दस-दस कनैक्शन दे दिये, कहां है तो कह रहे जी अधिकारी हैं, वो जो लगाने वाले हैं उनके खिलाफ एक्शन लेंगे देखेंगे। पता नहीं वो कब देखेंगे, कब लेंगे, पर जो साधारण लोग हैं, जो सज्जन लोग हैं, जो माननीय केजरीवाल जी के सिपाही हैं, लोग उनमे आस्था रखते हैं, जो रिश्वत का सहारा नहीं लेना चाहते, उन लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है। मुझे उम्मीद है कि हममे से बहुत सारे लोगों की ये समस्या होगी और मंत्री महोदय हमारी बात को।

....व्यवधान....

श्री मदन लाल: ये बहुत ज्यादा और कई बार तो कई-कई आईडी लेने के बाद भी कई बार कई-कई शर्तें पूरी करने के बाद भी वो कनैक्शन नहीं दे रहे हैं। धन्यवाद, मुझे उम्मीद है हमारी इस बात को सरकार ध्यान से सुनकर एक्शन लेगी, थैंक्यू।

माननीय अध्यक्ष: श्री महेंद्र गोयल जी।

श्री महेंद्र गोयल: धन्यवाद अध्यक्ष जी, जो आपने मुझे अपने क्षेत्र की समस्या उठाने के लिये मौका दिया। अध्यक्ष जी, पिछले काफी समय से दिल्ली जल बोर्ड के अंदर काफी समस्यायें आ रही हैं। क्षेत्र की समस्या के लिये जहां पर सीवर लाइनें डली हुई हैं उनकी

साफ-सफाई के लिये पहले super sucker गाड़ी, recycle, और जोड़ा गाड़ी मिलती थी लेकिन काफी समय से हमारे क्षेत्र के लिये कोई टेंडर नहीं हो पा रहा है हमें कोई गाड़ियां नहीं मिल पा रही हैं जिससे की सीवरों की सफाई नहीं हो पा रही है। मेरे हिसाब से ये समस्या ज्यादातर अब दिल्ली के काफी एरिये के अंदर भी ये आई हुई है और सफाई के लिये कर्मचारी मिलते थे दिल्ली जल बोर्ड को, काम करने के लिये मिलते थे कहीं पर कोई पाइप लाइन टूट जाती थी तो उसके लिये कर्मचारी मिलते थे। कहीं पर कोई सीवर लाइन की दिक्कत आ जाती थी तो उसकी सफाई के लिये मिलते थे लेकिन काफी समय से दिल्ली की व्यवस्थाओं का बिल्कुल नाश करने का ठेका ले रखा है इस टाइम में। मैं तो माननीय जल मंत्री से वाइस चेयरमैन साहब से एक ये रिक्वेस्ट करता हूं दिल्ली में आप कहीं दें या ना दें लेकिन मेरी रिठाला विधानसभा के लिये super sucker गाड़ी का, जोड़ा गाड़ी का इंतजाम जरूर करवा दें क्योंकि मैं अपने क्षेत्र की समस्या को उठा रहा हूं और मैं तो कह रहा हूं दें सभी को, मैंने तो पूरी दिल्ली के लिये बोला है। लोगों के घरों के अंदर सीवर का पानी बैक मारने लगा है, गलियों के अंदर लैट्रिंग बह रही है, बीमारी फैल रही है, ब्याह-शादी तो किसी को करने की बहुत दूर की बात है इस समय में किसी के बुलावे पे या मौत के ऊपर भी गलियों के अंदर जाने में आदमी हिचकता है, ऐसी पोजिशन आ गई है।

माननीय अध्यक्षः चलिये महेंद्र जी हो गया।

श्री महेंद्र गोयलः तो माननीय अध्यक्ष जी, आपसे क्षेत्र की जनता की तरफ से ये हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रहा हूं माननीय मंत्री जी को वाइस चेयरमैन साहब को आदेश दें कि मेरे क्षेत्र के लिए super sucker गाड़ी का, जोड़ा गाड़ी का इंतज़ाम करें और काम करने के लिये लेबर भी प्रोवाइड करवायें। पहले बहुत काम होते थे सरकार ने बहुत काम किये हैं, लोग हम पर विश्वास रखते हैं इसीलिये काम के लिये, मतलब हमें तीन-तीन बार यहां पर विधानसभा के अंदर सरकार बनाने का काम किया है लोगों ने। कमी तो कहीं ना कहीं ऊपर से होगी। हम तो कह रहे हैं, मैं ये 280 के तहत कर रहा हूं अगले मौके के ऊपर बोल लूंगा। आपसे 105 गलियों के लिये मैंने रिक्वेस्ट की है और ये आज तक टेंडर नहीं हुआ।

माननीय अध्यक्षः महेंद्र जी जो विषय है उसी पर बोलिये।

श्री महेंद्र गोयलः मैं उसी के ऊपर, मैंने वही कहा चेयरमेन साहब से।

माननीय अध्यक्षः भई ये बहस का विषय नहीं, बहस का विषय नहीं है।

श्री महेंद्र गोयलः तो बस यही है मेरा कि मेरे क्षेत्र के लिये ये जोड़ा गाड़ी ये super sucker आप प्रोवाइड करवायें धन्यवाद, जय हिन्द, जय भारत और पूरी दिल्ली के लिये करवा दोगे तो पूरी दिल्ली की जनता आपका धन्यवाद करेगी क्योंकि आप हमारे माई-बाप हैं अध्यक्ष हैं इस विधानसभा के आप माननीय मंत्री जी को दे दो आदेश, जय हिन्द।

माननीय अध्यक्षः महेंद्र जी ने जो परेशानी रखी है जहां तक मुझे जानकारी है सभी विधायकों के क्षेत्र में परेशानी है,

....व्यवधान....

माननीय अध्यक्षः एक सैकेंड भई मैं अपनी बात पूरी कर लूं। प्रिसींपल सेक्रेटरी, ाइनांस जल बोर्ड का पैसा रिलीज नहीं कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी बोला था, बैठ जाइये महेंद्र जी।

....व्यवधान....

माननीय अध्यक्षः नहीं बैठ जाइये अब कुछ नहीं प्लीज़ और सुप्रीम कोर्ट में भी सरकार गई, आदेश के बावजूद भी अभी तक हाई कोर्ट सॉरी, आदेश के बावजूद भी हाई कोर्ट ने क्लीयर आदेश दिया उसके बावजूद भी पैसा आज तक रिलीज नहीं हुआ इसलिये जल बोर्ड का भट्टा बैठा पड़ा है, काम बंद है। ये जानकारी के लिये मैं कोई इसमें सफाई नहीं दे रहा हूं हमारी जानकारी के लिये ये स्थिति मैंने आपको बताई। श्री अब्दुल रहमान जी।

....व्यवधान....

माननीय अध्यक्षः चलिये श्री अब्दुल रहमान जी।

श्री अब्दुल रहमानः धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद आपने मुझे एक बड़े महत्वपूर्ण मुद्दे को उठाने के लिये मौका दिया। अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले भी एक बार इस मुद्दे को उठाया था आपके समक्ष, मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि मेरी विधानसभा में एक गांधी

कोएड नाम का स्कूल है अध्यक्ष महोदय जिसकी स्कूल आईडी है 1105249 अध्यक्ष महोदय ये स्कूल ब्रह्मपुरी में स्थित है इसे सरकार ने टेकओवर कर लिया और करने के बाद इसको नई बिल्डिंग बनाने का आदेश कर दिया गया चूंकि बिल्डिंग बड़ी जर्जर थी, इसकी बिल्कुल कमरे की छत गिर रही थी। तो तीन साल पहले इसका टेंडर हो गया, टेंडर 24 करोड़ रुपये का हुआ 100 कमरे इसमें बनाये जाने थे लेकिन लगातार कोशिश करने के बाद भी वो बन ना सका क्योंकि इसमें 36 पेड़ थे और पेड़ों को एक जगह से दूसरी जगह पर स्थानांतरित करना था। अध्यक्ष महोदय, इस स्कूल में 4 हज़ार बच्चे पढ़ते थे, इस स्कूल को स्थानांतरित करके दूसरे स्कूल एक सीलमपुर के अंदर पीली बिल्डिंग में पहुंचा दिया गया। 3 साल हो गये वो टेंडर लैप्स हुआ मैंने माननीय मंत्रीजी के समक्ष अपनी समस्या को भी रखा उन्होंने आदेश दिया कि जल्द से जल्द इस स्कूल को बनाया जाये। तो इसका रिडिजाइन हुआ और रिडिजाइन होकर रिटेंडर हुआ, रिटेंडर होने के बाद अब से लगभग 8 महीने पहले ये कह दिया गया कि दो महीने के अंदर-अंदर इसका काम शुरू कर दिया जायेगा लेकिन अध्यक्ष महोदय 4 हज़ार से घटकर केवल 534 बच्चे रह गये उस स्कूल में और अध्यक्ष महोदय आज तक उस स्कूल का काम शुरू नहीं हुआ और वो स्कूल इसी तरह पड़ा हुआ है। तो मेरी आपके माध्यम से रिक्वेस्ट है कि उस स्कूल का जल्द से जल्द काम शुरू कराया जा सके ताकि बच्चे वहां आसानी से आ सकें और अपनी पढ़ाई पूरी कर सकें । अध्यक्ष महोदय, एक और स्कूल का ही मैटर है मेरा उसको भी मंत्री महोदय ने अपने संज्ञान में लिया

लेकिन वो अभी तक पता नहीं अधिकारियों के कान पर जूं नहीं रेंगती या अधिकारी सुन नहीं रहे। स्कूल का नाम है सीआर दास स्कूल, सीलम पुर 1105020 उसकी स्कूल आईडी है। अध्यक्ष महोदय, सन 1974 में ये स्कूल बना और आज इसकी हालत ये हो गई है कि बिल्कुल जर्जर बिल्डिंग है। प्लास्टर गिर जाता है। कभी जो है वो स्कूल चूने लगता है बरसात में। बच्चों के बैठने की व्यवस्था सही नही है। अध्यक्ष महोदय, सालाना इस पर मैन्टीनेंस के नाम पर पीडब्ल्यूडी करोडो रूपया खर्च कर देती है। लेकिन आज तक इसका सुधार नहीं हो पाया है। मैं आपके माध्यम से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि इस स्कूल की भी नई बिल्डिंग तामीर की जाए ताकि वहां भी बच्चे आसानी से पढ़ सकें। बस मैं ये ही दो रिक्वेस्ट करना चाहता था, अध्यक्ष महोदय। आपने सुना इसके लिए धन्यवाद। बहुत-बहुत शुक्रिया।

माननीय अध्यक्षः श्रीमान रामवीर सिंह बिधूडी जी।

श्री रामवीर सिंह बिधूडी (माननीय नेता, प्रतिपक्ष): आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से श्री अरविंद केजरीवाल जी की सरकार का ध्यान डीटीसी में कार्य कर रहे हजारों कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों की ओर, दिल्ली के स्कूल्स में लगभग जो बीस हजार गैस्ट टीचर्स काम कर रहे हैं, आंगनवाडी महिलाओं की ओर, आशा वर्क्स की ओर, होमगार्ड के कर्मचारियों की ओर और डीटीसी से जो मार्शल्स हटा दिये गए हैं उनकी ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं और दिल्ली सरकार के अन्य विभागों में भी हजारों कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी हैं। श्री अरविंद केजरीवाल की सरकार ने और दिल्ली के मुख्य मंत्री श्री अरविंद

केजरीवाल जी ने अनेकों बार ये वायदा किया था कि गेस्ट टीचर्स को नियमित किया जायेगा और दिल्ली के अंदर जो भी कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स है उनकी सरकार उनको नियमित करेगी। लेकिन मुझे कहते हुए दुःख हो रहा है कि पिछले नौ सालों में श्री अरविन्द केजरीवाल की सरकार अपने वायदे को पूरा नहीं कर पाई और निरन्तर ये लाखों लोग मुझे लीडर ऑफ ओपोजिशन के नाते मिलते हैं और मुझसे आग्रह करते हैं कि हमारे इन मुद्दों को आप विधान सभा के अंदर आदरणीय अध्यक्ष महोदय के माध्यम से दिल्ली के ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर के नोटिस में लाये। तो मैं आज आपके माध्यम से दिल्ली के ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर और जो हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर्स यहां बैठे हुए हैं मैं इन लाखों कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों की ओर से आग्रह करता हूं कि सरकार अपने वायदे के मुताबिक इन सभी को नियमित करे और डीटीसी के जो भूतपूर्व कर्मचारी है या जो रिटायर्ड हो गए हैं, उनको समय पर पेंशन नहीं दी जाती है। अनेक तरह की मुश्किलें उनके सामने आती है और वो फिर दिल्ली सरकार के खिलाफ धरना और प्रदर्शन करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं होनी चाहिए। मैं ये आपके माध्यम से क्योंकि यहां ऑनरेबल ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर बैठे हुए हैं। शायद उन्होंने इस सम्बन्ध में कोई कदम उठाया भी है लेकिन समय पर कर्मचारियों को या जो हमारे रिटायर्ड कर्मचारी है उनको उनका वेतन और उनकी पेंशन मिलनी चाहिए। मैं ये ही बातें आपके माध्यम से दिल्ली सरकार और दिल्ली सरकार के माननीय मुख्य मंत्री और जो हमारे अन्य ऑनरेबल मिनिस्टर्स हैं इन समस्याओं की ओर उनका ध्यान आकर्षित करना चाहता था। आपने मुझे समय दिया बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री राजेन्द्र पाल गौतमः आदरणीय अध्यक्ष जी, एक बात कहनी है। अभी जो विपक्ष के नेता बोल रहे हैं। हमारा पूरा सदन, पूरी सरकार सारे जितने भी कॉन्ट्रेक्ट पर नौकरी कर रहे हैं उनको पक्का करने को तैयार है क्या एलजी साहब से इसको ओके करवायेंगे, क्या बीजेपी इसमें साथ देगी? ये वादा करें कि बीजेपी साथ दे इसमें और सारे कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को पक्का करवाये। आम आदमी पार्टी की सरकार किसी भी तरह ठेकेदारी प्रथा के समर्थन में नहीं है, उसको खत्म करना चाहती है। मुझे आज भी याद है माननीय मुख्यमंत्री जी का आधे से ज्यादा भाषण छत्रसाल स्टेडियम के अंदर 15 अगस्त के दिन का भाषण है। आधे से ज्यादा भाषण इस पर था कि हम कच्चे कर्मचारियों को पक्का करेंगे और वो पक्का करना चाहते हैं। कुछ टीचरों को पक्का करने का प्रस्ताव केबिनेट ने पास किया था। लेकिन बीजेपी ने साथ नहीं दिया। इनके एलजी ने साथ नहीं दिया। क्या ये लीडर ऑफ ओपोजिशन इसका वायदा करेंगे कि उनको पक्का कराने में साथ देंगे। एलजी इनके हैं, ये पक्का कराने का वायदा करें हम इनके साथ हैं। मैं इसको प्रस्ताव को ला रहा हूं। मैं इस प्रस्ताव को ला रहा हूं कि उनको पक्का करने के लिए सरकार तैयार है। पूरा सदन तैयार है। पूछ लीजिए सारे सदस्यों से, एक भी सदस्य इसके खिलाफ नहीं है। सब चाहते हैं कि सारे कच्चे कर्मचारी पक्के होने चाहिए। क्या ये तैयार है। ये वायदा करें सबके सामने। धन्यवाद।

....व्यवधान....

माननीय अध्यक्षः बैठिए-बैठिए।

श्री राजेन्द्र पाल गौतमः सर सर्विसेज डिपार्टमेंट इन्होंने छीना है अवैध तरीके से। सुप्रीम कोर्ट से सर्विसेज डिपार्टमेंट मिला था। इन्होंने अवैध तरीके से संसद में बिल लाकर छीन लिया।

माननीय अध्यक्षः गौतम जी।

श्री राजेन्द्र पाल गौतमः और आज सर्विस डिपार्टमेंट इनके पास है तो ये वायदा करें, करवाये पक्का।

माननीय अध्यक्षः गौतम जी एक सैकेंड।

....व्यवधान....

माननीय अध्यक्षः मेरी बात सुन लीजिए। मैं कुछ कह रहा हूं।

....व्यवधान....

माननीय अध्यक्षः गौतम जी। एक राईटिंग में मैं आग्रह कर रहा हूं। एक राईटिंग में प्रस्ताव दीजिए उस पर चर्चा करवा देंगे। एक राईटिंग में प्रस्ताव दीजिए।

....व्यवधान....

माननीय अध्यक्षः मैंने बोल दिया है मैं बोल रहा हूं, ये ही बात बोल रहा हूं। हाँ माननीय मंत्री जी।

माननीय स्वास्थ्य एवं सेवाएं मंत्री (श्री सौरभ भारद्वाज): अध्यक्ष जी एक छोटी सी बात क्योंकि यहां पर ये मामला उठा है तो सरकार की तरफ से मैं ये बात रखना चाहता हूं कि ये जो कई हजार

सिविल डिफेंस वालेंटियर्स को साढे चौदह हजार क्योंकि मैं नम्बर नहीं जानता इसलिए मैं उसको बहुत स्पेशिफिक नहीं कहना चाहता, कई हजार सिविल डिफेंस वॉलेंटियर गरीब परिवार से आने वाले, बस मार्शल की तरह हमारे यहां काम कर रहे थे और बड़ा अच्छा काम कर रहे थे। जिस तरीके से उनको निकाला गया है, ये सदन उस विषय के ऊपर चर्चा करना चाहता है और प्रस्ताव पास करना चाहता है। तो आपसे हम लोग मिलेंगे तो आप हमें समय दीजिएगा। मेरी बिधूडी जी से सिर्फ करबद्ध निवेदन ये रहेगा कि आप इसके लिए अपनी तरफ से ठोस तैयारी करके आईयेगा और बताईयेगा कि आप अपने एलजी साहब से इस विषय में क्या करा सकते हैं जो हमसे सरकार द्वारा कराया जा सकता है आप वो बात बोल दीजिएगा इस सदन में कि ये काम सरकार कर दे और हम बोल देंगे ये काम आपके एलजी कर दें। आप तैयार हो, हम तैयार हों हजारों बच्चे वापिस आ जायेंगे। आप एक समय रख दीजिएगा।

....व्यवधान....

माननीय अध्यक्षः नहीं मैने बोला ना प्रस्ताव आ जायेगा फिर चर्चा करवायेंगे।

....व्यवधान....

माननीय अध्यक्षः नहीं मंत्री जी ने उत्तर दिया है। आपने अपनी बात रखी। मंत्री को अधिकार है ये चर्चा का नहीं है। 280 में चर्चा नहीं होती।

श्री रामवीर सिंह बिधूडी (माननीय नेता प्रतिपक्ष): उन्होंने जवाब मांगा है।

माननीय अध्यक्षः आपकी चर्चा होगी। चर्चा होगी, चर्चा पर..

....व्यवधान....

श्री रामवीर सिंह बिधूडी (माननीय नेता, प्रतिपक्ष): उन्होंने जवाब मांगा है तो जवाब दे दें।

माननीय अध्यक्षः देखिये उन्होंने ये कहा है प्रस्ताव लायेंगे। प्रस्ताव पर चर्चा होगी और उस वक्त बिधूडी जी ठोस जवाब तैयारी करके आयें। ठोस जवाब दें। हम अपनी बात पूरी करेंगे, बिधूडी जी अपनी बात पूरी करनी है। आज उत्तर नहीं मांगा। आपकी बात का, 280 का उन्होंने उत्तर दिया है। उसको एक-एक शब्दों को..

....व्यवधान....

माननीय अध्यक्षः बिधूडी जी आप बहुत शालीन आदमी हैं। इस पर चर्चा करेंगे, सारा सदन..

....व्यवधान....

श्री रामवीर सिंह बिधूडीः मैं कोई आरोप प्रत्यारोप करने के लिए खडा नहीं हुआ हूं।..

माननीय अध्यक्षः कोई बात नहीं। उस पर प्रस्ताव आयेगा, चर्चा करवाऊंगा।

श्री रामबीर सिंह बिधूडीः लेकिन मेरी भावना इतनी है कि दिल्ली सरकार की भी जो भावना है.

माननीय अध्यक्षः वो ही भावना उन्होंने व्यक्त की है।

श्री रामवीर सिंह बिधूडीः कि गरीब लोगों के साथ न्याय हो। क्योंकि उनके साथ कोमिटमेंट है और उस पर जिस तरह का सहयोग हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर ने जो कहा है लीडर ऑफ ओपोजिशन से आप उम्मीद करते हो, मेरा सहयोग पूरी तरह से मिलेगा।

माननीय अध्यक्षः चलिये। श्री अजय दत्त जी। जय भगवान जी आ गये हैं क्या?

श्री अजय दत्तः धन्यवाद अध्यक्ष जी आपने मुझे मेरे क्षेत्र के बहुत ही गम्भीर मुद्दे पर बोलने का मौका दिया। अध्यक्ष जी, अम्बेडकर नगर में काफी समय से एमबी रोड से होती हुई एक मैट्रो लाईन का निर्माण चल रहा है ऑलमोस्ट इसको पांच साल हो गए हैं। ये निर्माण कार्य बहुत ही धीमी गति से रेंग रहा है जिसकी वजह से आये दिन यहां जमा लगे रहते हैं। घंटों जाम होते हैं। आये दिन यहां पर खानपुर देवली रोड के जो मेरी constituency के निवासी हैं परेशान रहते हैं। उनके बच्चों को जब स्कूल छोडने जाते हैं तो प्रोब्लम होती है। जब बरसात का समय आता है तो वहां सारे नाले भर जाते है, ओवर फ्लो हो जाता है और आरपीएस एक कालोनी है उसमें पूरा पानी और मल जमा हो जाता है। इसके लिए मैंने कई बार मैट्रो को लिखा। मैट्रो के अधिकारियों से बात की लेकिन उन्होंने कोई संज्ञान नहीं लिया। अब

गर्मी का समय आता जा रहा है। कई बार तो ऐसा देखने में आया है कि स्कूल के बच्चे एक-एक डेढ-डेढ घंटे तक जाम में खड़े हुए है और कई बच्चे बेहोश हो गए। कई बार ऐसा देखने में आया है कि जाम की वजह से एम्बूलेंस नहीं आ पा रही है। लोगों को बहुत भारी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा मैट्रो ने जो गांव के आसपास की जमीन थी वहां कुछ झुग्गियां भी थीं उनको तोड दिया लेकिन झुग्गी वालों को कोई भी मुआवजा नहीं दिया। बंजारा कैम्प की ये झुग्गियां है। मैने इस पर डयूसिब से बात की तो पहले मैट्रो ने वो डयूसिब को भेज दिया फिर डयूसिब ने मैट्रो को भेज दिया ये दोनों आपस में खेल रहे हैं। जिन लोगों की झुग्गियां टूटी हैं वो आज भी बेचारे बेघर घूम रहे है। मैं आपके माध्यम से डयूसिब को और मैट्रो को ये कहना चाहता हूं कि उनका मुआवजा जल्दी दिया जाये। क्योंकि वो लोग कहां जायेंगे जिनकी आपने झुग्गियां तोडी है, जिनकी छोटी मोटी दुकानें तोड़ी हैं। खान पुर गांव के बहुत सारे लोग जिनके घर इस मैट्रो लाईन में आ रहे हैं वो काफी समय से मैट्रो से बातचीत कर रहे हैं। खानपुर गांव के लोगों को मुआवजा भी नहीं मिल रहा है और उनको जो मुआवजा देने के लिए मैट्रो कह रही है वो भी ओने-पौने दाम पर है। अध्यक्ष जी, जो खान पुर गांव के लोगों की पुश्तैनी जमीनें हैं उन जमीनों का मुआवजा आज के रेट पर, सर्कल रेट से भी ज्यादा का वहां है। तो उनको जो बैस्ट मुआवजा है वो दिया जाए और ये खान पुर गांव से होती हुई, एमबी रोड से होती हुई जो मैट्रो लाईन है इसको जल्दी किया जाए क्योंकि अब ये देखने में आया है दिल्ली के अंदर

पहले जो काम दो साल का इनका प्रोजेक्ट होता था वो ढाई साल में हो जाता था, अब दो साल का प्रोजेक्ट पांच साल में भी मुझे लग रहा है ये नहीं कर पा रहे हैं जिसकी वजह से पूरे खान पुर एमबी रोड पर बदरपुर से लेकर महरौली तक इतना जाम लगता है, दो-दो, ढाई-ढाई घंटे लोगों को सफर करना पड़ता है। ये सिर्फ और सिर्फ नाकामी है मैट्रो की। तो मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि आप मैट्रो के अधिकारियों को ये दिशा निर्देश दें कि भई उस काम को जल्दी से जल्दी कीजिए क्योंकि जो पैसा दिल्ली सरकार को देना था वो ऑलरेडी दे चुके हैं और केन्द्र सरकार का पता नहीं क्या चल रहा है। लेकिन इनकी वजह से जो ये जितने भी हमारे खांनपुर गांव के एमबी रोड के तुगलकाबाद के हमारे विधायक बैठे हैं, देवली के विधायक बैठे हैं ये सबके पूरी की पूरी ये जो एमबी रोड की व्यवस्था खराब हो चुकी है। तो मेरा आपसे निवेदन है कि मैट्रो से कहें कि खांनपुर गांव के लोगों का मुआवजा टाइम पर दे दें और जो झुग्गियां उन्होंने तोडी हैं वो उनका मुआवजा टाइम पर दें दे और ये काम को जल्दी से जल्दी करायें जिससे आरपीएस कालोनी में पानी ना भरे और जल्दी लोगों को सुविधा मिले। आपने मुझे मेरे क्षेत्र के मुद्दे पर बोलने का मौका दिया अध्यक्ष जी। मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं। जय हिंद। जय भारत।

माननीय अध्यक्षः कादियान जी।

श्री वीरेंद्र सिंह कादियानः अध्यक्ष महोदय, दिल्ली कैंट विधान सभा क्षेत्र में दो झुग्गियां हैं किर्बी प्लेस और बरार स्केयर। अध्यक्ष महोदय उन दोनों ही झुग्गियों में पिछले लगभग पच्चीस वर्षो से बिजली

नहीं है और न ही कोई पानी की व्यवस्था है। इस मुद्दे को मैं पहले भी उठा चुका हूं। पत्र भी कई बार लिख चुका हूं अध्यक्ष महोदय कि वो झुग्गीवासी बिना बिजली के और बिना पानी के जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनसे वंचित हैं। अभी गर्मी आ जायेंगी अध्यक्ष महोदय, गर्मियों में तो बहुत बुरा हाल होता है। जब 44-45 डिग्री टैम्परेचर और उस टैम्परेचर में बिना बिजली के रहना बुजुर्गो को, बच्चों को बीमारों को तो बड़ा दिक्कत का काम होता है। आये दिन ये यू टयूबर घूमते रहते हैं। वो भी इसी चीज को उठाते हैं कि जी देखो जी आपके यहां पर क्या काम कर दिया। आज तक बिजली नहीं है, पानी नहीं है और वो इस लिए नहीं है अध्यक्ष महोदय कि वहां पर एनओसी नहीं मिलती। हमने पहले भी इस मुद्दे को सरकार के माध्यम से पहुंचाया, परन्तु उन झुग्गीवासियों का अभी तक कोई भला नहीं हुआ है। दूसरा अध्यक्ष महोदय कि किर्बी प्लेस के जो लोग हैं उन झुग्गीवासियों से लगभग 2010 में जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी तो उस समय पर झुग्गी के बदले मकान देने के लिए कुछ पैसे जमा कराये थे और लगभग चौदह साल हो गए अध्यक्ष महोदय उनको कोई ना तो मकान मिला है और न ही उनके पैसे का कोई हिसाब किताब अब तक पता चल पाया है। डयूसिब द्वारा ये पैसे लिये गए थे अध्यक्ष महोदय। तो उनको एक तो ये बताया जाये कि भई आपके जो पैसे जमा हैं उनके बदले उनको मकान या प्लॉट कब दिये जायेंगे। एक और मुख्य बात ये है अध्यक्ष महोदय बरार स्केयर झुग्गी है जहां पर रिंग रोड के पास में नारायणा रिंग रोड के पास, उसके लिए मैंने कई बार रिक्वेस्ट की है

कि भई वहां पर एक टयूबवेल लगा दिया जाए ताकि उन झुग्गीवासियों को कम से कम हमारे पीडब्ल्यूडी लैंड पर अगर हम टयूबवेल लगाते हैं तो पानी की सप्लाई होने से उनको पानी की कम से कम सुविधा प्राप्त हो सके। तो इस मुद्दे को भी जल बोर्ड अधिकारियों से और जो वाइस चेयरमैन है जल बोर्ड के उनको भी मैं कह चुका हूं। मंत्री जी को भी कह चुका हूं। बार–बार कहते हैं अध्यक्ष महोदय लेकिन एक टयूबवेल की सख्त जरूरत है ताकि गर्मियों में पानी की समस्या से निजात पा सके। बहुत–बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय।

माननीय अध्यक्षः श्री सुरेन्द्र कुमार जी।

श्री सुरेंद्र कुमारः माननीय अध्यक्ष जी, आपने गोकल पुर की एक गम्भीर समस्या पर बोलने का आपने मौका दिया, आपका धन्यवाद करता हूं। माननीय अध्यक्ष जी करीब दस साल से लगातार सदन का भी ध्यान गोकलपुर विधान सभा की इस समस्या की तरफ दिलाना चाहता हूं कि मेरी विधान सभा में करीब हर्ष विहार वार्ड में पच्चीस एकड जमीन है जिस जमीन में वहां पूरी कालोनी का पानी जल भराव हो जाता है। जल भराव होने की वजह से वहां पर अनेक बीमारियां उत्पन्न होती है। वहां पीछे अभी उधर मैं गया था उसके आसपास के एरिये में करीब पच्चीस व्यक्तियों को डेंगू हो गया, मलेरिया हो गया। तमाम बीमारियों से लोग ग्रस्त रहे। मैं कई बार वहां डीएम से भी मैं मिला, एसडीएम से भी मिला उनके साथ मीटिंग करी अपने एमसीडी कमिशनर से भी मीटिंग करी, डीसी से भी मीटिंग करी इसके बावजूद नगर निगम के पास जाते हैं तो डीसी हाथ उठाता है जी मेरे क्षेत्र का

मामला नहीं है, मेरे अधिकार का नही है। डीएम के पास जाते हैं डीएम भी मना कर देता है। कमिशनर ने तो बिल्कुल हाथ उठा दिए कि अनओथराइज कालोनी हमारे पास नहीं आती है। तो ये कई बार मिलने के बाद भी, अधिकारियों को लैटर भी लिखा, उनके पास गया भी लेकिन इस समस्या से निजात माननीय अध्यक्ष जी नहीं मिली है। ये एक बड़ी गंभीर समस्या है और ये दिल्ली सरकार कोई जमीन पीछे एलोटमेंट हुई थी लेकिन वो कोर्ट में जाने की वजह से वो अभी क्लियर नहीं हो पाई है। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि क्षेत्र के 50 हजार जनता क्षेत्र में रहती है वो सब इस जल भराव से ग्रस्त हैं, सब परेशान हैं। तो मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूं कि दिल्ली कमिशनर या डीएम को आप आदेश करें ताकि इस समस्या से उस क्षेत्र के लोगों को मुक्ति मिले। आपसे मेरी बार बार यही विनती है कि मैं करीब दो साल से लगातार इस क्षेत्र की समस्याओं को लेकर बार बार अधिकारियों के पास गया लेकिन अब तक उससे निजात नहीं मिली। ये एक बड़ी गंभीर समस्या है क्योंकि 25 एकड़ यानि कि सौ बीघे सवा सौ बीघे जमीन है वो चारों तरफ से घिरी है, पूरा पानी भरा हुआ है तो तमाम वहां सांप भी निकले हैं, कीड़े मकौड़े भी काफी निकल जाते हैं वहां से, कई बार तो सांप निकल कर घरों में घुस गए हैं। तो आपसे मेरा निवेदन ये है कि इस समस्या से इस क्षेत्र को आप निजात दिलाने की या मुक्ति दिलाने की कृपा करें। आपने मुझे अपनी बात रखने का मौका दिया जय भीम, जय भारत।

माननीय अध्यक्षः जय भगवान जी।

श्री जय भगवानः माननीय अध्यक्ष महोदय जी आपने 280 पर मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया उसके लिए धन्यवाद और मैं सदन का ध्यान और आपका ध्यान बवाना विधानसभा की तरफ ले जाना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मेरा जीओसी बुध विहार की मैं बात कर रहा हूं अध्यक्ष महोदय कि वहां पर हमारे सीवर लाइन का काम कंपलीट हो गया है लेकिन कुछ मेरे ब्लॉक हैं जे, एन, क्यू ब्लॉक उनके अंदर करीब करीब 18 गलियां हैं जिनमें सीवर लाइन नहीं डाली गई है और ग्राम सभा पूठकलां के अंदर 48 गलियों के अंदर सीवर लाइन नहीं डाली गई है जिसकी वजह से काफी दिक्कतें आ रही हैं, बहुत ज्यादा परेशानी झेलने को मिल रही है। अध्यक्ष महोदय, फिर दूसरा जीओसी जो मेरी बेगमपुर है उसके अंदर जो लैफ्टआउट पोर्शन है उसको लेकर के हमने जो फाइल पास कराई थी लेकिन जो ऐजेंसी है उसने काम स्ट्रार्ट नहीं किया जिसकी वजह से काम में काफी देरी हुई है जिसकी वजह से लोग काफी ज्यादा परेशान हैं, तो वहां पर उस कार्य को जल्दी से जल्दी चालू कराया जाए। दूसरा ऐजंसी के द्वारा रेस्टोरेशन का जो कार्य है वो नहीं किया जा रहा है वो भी जल्दी से जल्दी कराया जाए। तीसरा अध्यक्ष महोदय, मेरे सैक्टर 26 फेस फोर में एक छोटा सा पार्ट है मेरा सैक्टर 26 फेस फोर उसके अदंर सीवर का कार्य स्ट्रार्ट नहीं हो पा रहा है वो कह रहे हैं कि अलग से इस का प्रपोजल बनेगा। तो मेरा निवेदन है क्योंकि मैं कई बार, बार बार लिख कर दे चुका हूं तो उसमें भी इसी जो ओन गोइंग वर्क है इसी के अंदर काम चालू करा दिया जाए। अध्यक्ष महोदय मेरे चार पांच प्रोजेक्ट हैं मेरे

पंजाब कोड बाजीतपुर, सलाहपुर माजरा, औचंदी और नया बांसवा इनके अंदर ना टैण्डर स्टेज पर थे सारे काम और यहां पर टैण्डर लग के काम स्ट्रार्ट होना था जिसकी वजह से हमने कई जगह पर गलियां भी नहीं बनाई थी रोड़ों पे और पिछले एक साल से काम रूका हुआ है जिसकी वजह से इनके टैण्डर नहीं हो पा रहे हैं, तो इनके टैण्डर जल्दी से जल्दी हो जाएं अध्यक्ष महोदय, और अध्यक्ष महोदय एक बवाना डब्लयूटीपी से कुतुबगढ़ यूजीआर तक एक 700 एमएम की एक लाइन जानी है जिसकी वजह से अभी क्योंकि हमने वो रोड़ बनाया था अभी बवाना से लेकर औचंदी तक वो सारा रोड़ बार बार टूट रहा है जिसकी वजह से क्योंकि वो जो लाइन है पिछले तीस पैतींस साल पुरानी है, उस लाइन को जल्दी से जल्दी चेंज किया जाए। अध्यक्ष महोदय लास्ट है मेरा सैक्टर 23 यूजीआर और सैक्टर 29 और सैक्टर 36 अभी सैक्टर 29 और सैक्टर 23 के अंदर यूजीआर के अंदर हमें कम से कम 15 एमजीडी पानी की जरूरत है अध्यक्ष महोदय क्योंकि मेरा जो इलाका है इसके अंदर पिछले दस सालों के अंदर काफी पोपुलेशन बढ़ी है, काफी काम हुआ है मतलब अध्यक्ष महोदय दूसरा क्योंकि पानी की जो ऐलोकेशन है पिछले दस सालों से नहीं बढ़ाई गई जिसकी वजह से काफी दिक्कतें आ रही हैं वहां पर और काफी तादाद में मकान भी बन रहे हैं अध्यक्ष महोदय और एक करीब सैक्टर 36 के अंदर हमने एक यूजीआर लिया है जिसके अंदर पांच एमजीडी की जरूरत है पानी की क्योंकि मेरे जो इलाके हैं नवीन विहार और राजीव नगर एक्सटैंशन उसके अंदर मैंने पानी की लाइन डाली है लेकिन पानी ना होने की

वजह से मैं उनको पानी नहीं दे पा रहा हूं पिछले दो सालों से। तो मेरा निवेदन है जो मैं यहां पर बोल रहा हूं अध्यक्ष महोदय, इस पर इंपलीमेंट किया जाए क्योंकि काफी परेशानी है। आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया इसके लिए धन्यवाद।

माननीय अध्यक्षः श्री सोमनाथ भारती जी।

श्री सोमनाथ भारतीः अध्यक्ष महोदय आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने 280 में मुझे बोलने का मौका दिया। अध्यक्ष महोदय जब आज रामवीर सिंह जी बिधूड़ी बोल रहे थे चूंकि इसी से कनैक्टिड है वो, तो ये दोनों तरफ से चलते हैं, पहले काम रोकते हैं और उसके उपर फिर ये हमारी निंदा करना चाहते हैं। उसी का एक मैं आज आपके सामने उदाहरण रखूंगा। जब दिल्ली में एमसीडी के अंदर आम आदमी पार्टी को जनता ले के आई तो बहुत उम्मीदें बंधी हुई थीं, उसमें एक उम्मीद थी कि सारी दिल्ली की सड़के, गलियां, नालियां सब बन जाएगीं। माननीय केजरीवाल साहब के नेतृत्व में जो एक फंड हमें मिला था मुख्यमंत्री सड़क पुर्न निर्माण योजना जिसके तहत दिल्ली के सारे विधायकों ने, सारे पार्षदों ने बहुत सारी रिकवेस्ट सड़कों की, गलियों की पूरी करने के लिए लगा दी। ये फंड एक्सकलूसिव इस परपस के लिए था कि दिल्ली की सड़कें बन सके, दिल्ली की गलियां बन सकें लेकिन इस भाव से कि अगर दिल्ली में सड़कें और गलियां बन गई तो एमसीडी के अंदर आम आदमी पार्टी का नाम हो जाएगा। मैं सारे विधायकों का ध्यान चाहता हूं इसके उपर अब एमएसपीवाई जो योजना थी जिसमें 300 करोड़ रूपये इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री ने दिया

था कि सारे विधायक गण अपने अपने गलियों का, सड़कों का लेखा जोखा लगाएं और उसको पूरी करवाएं। अब जनता बड़ी भोली भाली होती है चूंकि जनता को हमने यही कहा था कि एमसीडी में हमें ला दो, हम सारी गलियां बना देगें, सारी सड़कें बना देगें। ऐसी ऐसी गलियां थीं, ऐसी ऐसी सड़कें थी जो 15 बीस साल से नहीं बनी। भाजपा 15 साल से एमसीडी के अंदर थी कोई सड़क ना बना पाई। तो ये जो उम्मीदें जनता की थी अब ये जब पूरी होने वाली थीं तुरंत ही भाजपा का शिकंजा चला और माननीय एलजी साहब के आफिस का दुरूपयोग करते हुए एमएसपीवाई योजना को इन्होंने कहा कि जी ये तो विदाउट कैबिनेट एप्रूवल है। ये क्या तरीका है? मतलब कोई स्कीम चल रही है बरसों से, दशकों से अचानक दिल्ली की जनता को तंग करने के लिए कि दिल्ली की जनता की खराब सड़कें बन ना पाएं, खराब गलियां बन ना पाएं, दिल्ली के विधायक, दिल्ली के पार्षद जो आम आदमी पार्टी के हैं चूंकि मैजोरिटी उनकी है इसलिए उनकी थू-थू हो उनके आगे जो जनता ने उम्मीदें रखी थीं वो पूरी ना कर पाएं इसलिए आपने इस पूरे स्कीम को खत्म कर दिया। फिर क्या हुआ? विधायक निधि फंड बहुत कम होता है अब चार करोड़ के फंड में कितना काम करा लोगे? अध्यक्ष महोदय, मेरे यहां सफदरजंग एंकलेव है, मेरे यहां ग्रीन पार्क एक्सटेंशन, ग्रीन पार्क मेन, शिवालिक इतनी सारी कालोनियां हैं। गुलमोहर पार्क, नीति बाग सब जगह हमने जो उम्मीदें बांध के दी थीं कि जी हमारी एमसीडी में सरकार जैसे ही बन जाएगीं वैसे ही सारी की सारी सड़कें बनवा दूंगा, सारी गलियां बनवा दूंगा, लेकिन हुआ क्या? ये सारे

ऐस्टीमेट बन के वहां रह गए अब ये एमएसपीवाई इन्होंने खत्म कर दिया। जनता तो ये भी नहीं जानती कि एमएसपीवाई क्या चीज होती है और जनता को बोलो एमएसपीवाई भी खत्म हो गया है, भई एमएसपीवाई क्या चीज होती है। सोमनाथ जी आपने तो कहा था कि एमसीडी में वोट हमको दे दो, हमारे काउंसिलर ले आओ, सारी सड़कें बनवा देंगे। अब जनता को नहीं मालूम कि एमएसपीवाई क्या चीज होती है। तो मैं आज इस सदन के माध्यम से, आपके माध्यम से दिल्ली की जनता को कहना चाहता हूं कि माननीय केजरीवाल साहब के अथक प्रयासों के बावजूद आपके विधायक, आपके पार्षद जो आम आदमी पार्टी के हैं, अथक प्रयासों के बावजूद भाजपा ने षड्यंत्र करके एमएसपीवाई मुख्यमंत्री सड़क पुनर्निर्माण योजना जो था उसको खत्म कर दिया, जिसके कारण हम आपकी सड़कें और नालियां और गलियां बनाने में थोड़ा डिले हो रहा है, प्रयास कर रहे हैं कि विधायक निधि फंड से उसको बनवा दिया जाये लेकिन विधायक निधि फंड में पैसा ही नहीं है। हम तो उसमें बड़ा धन्यवाद करते हैं माननीय मुख्यमंत्री को कि उन्होंने हम लोगों की रिक्वेस्ट पे तीन तीन करोड़ रूपया और दिया हमें एमएलए लैड फंड में। माननीय सौरभ जी सुन ही रहे हैं। तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि चूंकि ये सदन ही है जिसके जरिये हम जनता तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, हम सब पीड़ित हैं इस बात से। तो मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं two fold पहला कि ये जो एमएसपीवाई क्यों इन्होंने खत्म किया, किस आधार पे खत्म किया, क्या इनकी मर्जी चलेगी, दिल्ली की जनता ने अगर केजरीवाल जी को चुना है तो केजरीवाल जी के आदेश को नहीं माना जायेगा जो

चुने विधायक हैं उनकी रिकवेस्ट को नहीं माना जायेगा? ये भाजपा बताये कि एमएसपीवाई योजना के तहत जो सड़कें और गलियां बनने वाली थी, जो क्षेत्र की जनता को सुविधायें मिलने वाली थीं, जो बेचारे बुजुर्ग गिर रहे हैं, बच्चे गिर रहे हैं खराब सड़कों के कारण, 15 साल में भाजपा ने एक सड़क नहीं बनाया हमारे यहां। तो आज मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि इस सरकार से पूछें कि भई एमएसपीवाई योजना क्यों बीच में छोड़ दी गयी, क्यों उसको रोक दिया गया नंबर वन? नंबर टू अध्यक्ष महोदय, चूंकि ये तो खेल खेल ही रहे हैं, चूंकि जैसा राजेन्द्र पाल गौतम जी ने कहा सारा तोते का जान तो सर्विसिस के मैटर में है।

माननीय अध्यक्षः सोमनाथ जी कंक्ल्यूड करिये।

श्री सोमनाथ भारतीः सर्विसिस के मैटर को जब तक सॉल्व नहीं करेंगे तब तक दिक्कत रहेगा। अध्यक्ष महोदय,..

माननीय अध्यक्षः सोमनाथ जी अब कंक्ल्यूड करिये प्लीज।

श्री सोम नाथ भारतीः सेकिंड फोल्ड कि मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि इस बार जब सरकार बजट लेके आ रही है तो उसमें विधायक निधि फंड 10 करोड़ कर दिया जाये जिससे कि हमारी जो सड़कें हैं, चलो 10 तो मान लें, भई मानिये सौरभ जी हम कह रहे हैं 10 करोड़ कर दिया जाये इस बार विधायक निधि फंड जिससे कि हमारा इस बार सड़कें, गलियां बन जायें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्यू, धन्यवाद।

माननीय अध्यक्षः अब श्रीमान सौरभ जी माननीय मंत्री, उर्जा विभाग से संबंधित कार्यसूची के बिंदू क्रमांक 2 में दर्शाये गये दस्तावेजों की प्रतियां सदन पटल पर प्रस्तुत करेंगे।

श्री सौरभ भारद्वाज (माननीय उर्जा मंत्री): अध्यक्ष महोदय, क्योंकि आतिशी अभी हाउस में नहीं हैं तो उनकी तरफ से मैं आपकी अनुमति चाहता हूं with your permission, I would like to lay the papers as mentioned in point number 2 of today"s list before this House.

2. i) दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (उपभोक्ता की शिकायत के निवारण के लिए मंच और ओम्बुडसमैन) (द्वितीय संशोधन) विनियम, 2023 के संदर्भ में दिल्ली राजपत्र (असाधारण, भाग–3)में जारी अधिसूचना संख्या एफ.11 (1938)/डीईआरसी/2021–22/7263/1011 दिनांक 01.08.2023 (हिंदी एवं अंग्रेजी प्रति)[1]

ii) दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (उपभोक्ता की शिकायत के निवारण के लिए मंच और ओम्बुडसमैन) (द्वितीय संशोधन) विनियम, 2023 के संदर्भ में दिल्ली राजपत्र (असाधारण, भाग–3) में जारी शुद्धिपत्र संख्या एफ.11(1938)/डीईआरसी/2021–22/7263/2199 दिनांक 19.01.2024 (हिंदी एवं अंग्रेजी प्रति)[2]

iii) दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (डीईआरसी) वर्ष 2020–21 हेतु वार्षिक प्रतिवेदन की प्रति (हिंदी एवं अंग्रेजी)[3]

---

[1] दिल्ली विधान सभा पुस्तकालय में संदर्भ संख्या आर-23261 पर उपलब्ध।

[2] दिल्ली विधान सभा पुस्तकालय में संदर्भ संख्या आर-23262 पर उपलब्ध।

[3] दिल्ली विधान सभा पुस्तकालय में संदर्भ संख्या आर-23263 पर उपलब्ध।

माननीय अध्यक्षः अब श्री सोम नाथ भारती जी माननीय सदस्य पानी के बिलों पर दिल्ली सरकार की एकमुश्त निपटान योजना को संबंधित अधिकारियों द्वारा रोके जाने के संबंध में नियम 54 के अन्तर्गत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव रखेंगे।

श्री सोमनाथ भारतीः माननीय अध्यक्ष महोदय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपने इतने गंभीर मुद्दे को सदन में उठाने का मौका दिया। अध्यक्ष महोदय, दिल्ली सरकार माननीय केजरीवाल साहब के नेतृत्व में जिस दिन से चल रही है भाजपा हर प्रकार के अड़ंगे लगा रही है जिससे कि जनता में रोष पैदा हो। पूरी दिल्ली के अंदर चूंकि कोरोना काल के दौरान वाटर मीटर रीडर घर घरजा न सके, मीटर रीडिंग नोट न कर सके इस करके वाटर मीटर रीडर्स घर बैठे, आफिस बैठे, बगैर क्षेत्र में गये उन्होंने या तो उसको लिख दिया कि नो मीटर अवेलेबल और बगैर मीटर का एवरेज पे बना दिया बिल या फिर अनाप शनाप कोई रीडिंग लिख दी उसके अंदर। अब जहां बिल आ रहा था जीरो, वहां हो गया 2 हजार, 3 हजार, 4 हजार, 5 हजार। तो जनता को लगा कि केजरीवाल जी ने तो कहा था कि हमारा बिल जीरो है। बीस हजार लीटर के नीचे नीचे मैं पानी खत्म करता हूं हर महीने। तो जो बिल जीरो आ रहा था वो अचानक हजार रूपया, दो हजार रूपया कैसे हो गया। इस कारण से जनता ने पे करना बंद कर दिया। विधायकों के पास आने लगे, हमें चेज़ करने लगे, हमें बोलने लगे और उनका रिकवेस्ट जेनुइन था। उसके बाद हमारी सरकार ने केजरीवाल साहब के नेतृत्व में ये फैसला लिया कि इसका समाधान लाना चाहिये। हम माफी

की बात नहीं कर रहे। हम बात कर रहे हैं बिल करेक्शन की चूंकि जो आज के तारीख में पानी जेनुइनली कंज्यूम कर रहा है, उसको उसी अनुसार, उसी प्रपोर्शन में बिल आना चाहिये। तो जो व्यक्ति दिल्ली के अंदर माननीय केजरीवाल साहब की स्कीम के अन्तर्गत 20 हजार लीटर पानी प्रति महीना से कम खर्च करता है उसका बिल जीरो आता है। तो जब ये स्कीम है, ये चुनी हुई सरकार की मंशा है, ये चुनी हुई सरकार की दिल्ली को देन है तो नैचुरल सी बात है उस जनता को इस बात की उम्मीद होगी कि मेरे बिल को करेक्ट किया जाएगा। तो ये चूंकि जब से मुझे जलबोर्ड का वाईस चेयरमैन बनाया गया है मैं तब से देख रहा हूं कि जितने भी निर्देश दिल्ली जलबोर्ड के कर्मचारियों को दिये जायें, अधिकारियों को दिये जायें उसको मानने में टालमटोल करते हैं। इसका कारण क्या रहा है, जो गौतम जी ने आज कहा कि सारी मुसीबत की जड़ सर्विसिस डिपार्टमेंट है जो 11 मई 2023 को आठ साल की कानूनी लड़ाई के बाद माननीय उच्चतम न्यायालय ने दिया था अरविंद केजरीवाल जी को। लेकिन जस्ट एक सप्ताह बाद ये कायर भाजपा 19 मई 2023 को एक आर्डिनेंस लाकर के उसको छीन दिया। ये क्या छीना? ये ताकत केजरीवाल से नहीं छीनी, ये ताकत दिल्ली की जनता से छीनी, ये जो अपमान हुआ वो दिल्ली की जनता का हुआ और उसी का परिणाम ये है कि जो दिल्ली जलबोर्ड के बिल सेटलमेंट स्कीम जिसको बहुत जद्दोजहद के बाद बड़े तरीके से, बड़े एनलाईज करके हम लेकर के आये, माननीय मंत्री जी ने इसका बकायदा खाका तैयार किया, पूरा डिस्कशन हुआ, पूरा डिबेट हुआ, अधिकारियों के साथ

बातचीत हुई कि देखो जी हम माफी की बात नहीं कर रहे, हम ये बात कर रहे हैं कि बिल को करेक्ट करना पड़े कि जिस प्रपोर्शन में जनता ने पानी कंज्यूम किया है, उसी प्रपोर्शन में जनता का बिल आना चाहिये। अगर 20 हजार लीटर या उससे कम किया है तो बिल जीरो आना चाहिये, जो पहले आ रहा था। तो इस प्रकार से दिल्ली में हाहाकार मचा। हमने कहा कि अगर किसी भी तरह से एक साल का बिल देख लें, अगर पिछले एक साल में, पिछले 12 महीनों में कोई एक बिल अगर सही आया हो उस जनता के अनुसार, तो उसको बेस मान लिया जाये और उसी आधार पे बाकी सारे जितने रीडिंग्स हैं उसको बराबर कर दिया जाये। अगर एक साल में न आता हो तो दो साल देख लो, अगर दो साल में न आता हो तो 5 साल देख लो। कभी तो कोई करेक्ट रीडिंग आई होगी। तो करेक्ट रीडिंग के अनुसार उसको हम proportiona जमकर देंगे और extrapola जम कर देंगे बाकि सारे महीनों के ऊपर भी। इससे अच्छी बिल क्या हो सकती है, ये तो पढ़े लिखो का बिल है, ये पढ़े लिखो का सेटलमेंट स्कीम है। अध्यक्ष महोदय, और अगर मान लीजिए कि कोई भी करेक्ट बिल नहीं आया, कोई भी करेक्ट उसमें रीडिंग नहीं आई तो हमने कहा कि भई आप अपने नेबरहुड में देख ले, अगर उसी साइज का मकान और उसी number of families, let say number of family members का वो कोई फैमिली वहां पर है उसका कंजम्पशन देख ले, उसके ऊपर उसको extrapolate करें। ऐसे स्कीम को जिसके तहत अगर ये अप्लाई कर दिया जाएगा तो पूरे दिल्ली में दो बड़ी चीजों का समाधान होगा, पहली

बात जनता में जो असंतोष पैदा हो गया है, जनता में जो अविश्वास पैदा हो गया है दिल्ली जल बोर्ड के बिलों को लेकर के उसका समाधान होगा, साथ में जो दिल्ली जल बोर्ड में रेवेन्यू आना कम हो गया है, चूंकि ये बिल अनाप-शनाप आ रहे हैं तो लोग कह रहे हैं भई जब ठीक होगा तब देखेंगे हम, तो दिल्ली जल बोर्ड के रेवेन्यू का भी एक बहुत बड़ा स्रोत बन पायेगा जब ये स्कीम इम्प्लीमेंट कर दिया जायेगा। अब यूडी मिनिस्टर- माननीय सौरभ भारद्वाज जी ने चूंकि यूडी डिपार्टमेंट हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट है जल बोर्ड का, इस पूरे स्कीम को यूडी-सेक्रेटरी को कहा कि भई इसको आप कैबिनेट नोट बनाकर पेश करिये। आप सोच सकते हैं, कहीं ऐसा होता होगा, ये यूडी-सेक्रेटरी की हिम्मत, ये उनकी हिम्मत नहीं है, ये भाजपा के डर का, भाजपा के दबाव का चक्कर है सारा। मैं मतलब सोच-सोचकर परेशान रहता हूं कि किस प्रकार से हमारी सरकार चल रही है। किस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री, माननीय मंत्रीगण सारे काम कर रहे हैं कि आज साथियों ने भी जो सदन के अंदर रखा, आपने भी ये बात कही, हाई कोर्ट का आदेश है, 6 फरवरी, 2024 का हाई कोर्ट का आदेश है कि एक सप्ताह के भीतर सारे फंड कांट्रेक्टर्स को रिलीज करो, वो एक सप्ताह निकल गया, अब ये वेट कर रहे हैं 29 तारीख का, मतलब everyday they are trying to just sit on that scheme, on that order of Hon'ble High Court अब 29 तारीख का वेट कर रहे हैं, शायद उसके एक-दो दिन पहले करेंगे, फिर जाकर माफी मांग लेंगे। हो क्या रहा है दिल्ली के अंदर, तो ये भाजपा बताये। माननीय बिधूड़ी जी भाजपा से

आते हैं, ये सरकार से बातचीत करें, एल.जी. साहब से बातचीत करें कि भई इस प्रकार से दिल्ली की जनता को तंग कर रहे हों, क्यों तंग कर रहे हों?

माननीय अध्यक्षः कंकलूड करिये सोमनाथ जी।

श्री सोमनाथ भारतीः तो मैं ये आपके जरिए आज सदन के अंदर कॉलिंग अटेंशन रखा है कि 'वन टाइम सेटलमेंट स्कीम' जो है, जिस प्रकार से भाजपा ने अपने ताकत का दुरूपयोग करके जो ऑर्डिनेंस और बाद में बिल बनाकर के, बाद में एक्ट बनाकर के ये ताकत ली है सर्विसेज का, उस ताकत का दुरूपयोग करके, यूडी-सेक्रेटरी के ऊपर दबाव डालकर के इस बिल का, स्कीम को कैबिनेट के सामने नहीं लेकर के आ रही है, मैं चाहता हूं कि आप इस पर चर्चा कराइये। धन्यवाद।

माननीय अध्यक्षः अब श्री राजेन्द्रपाल गौतम जी, माननीय सदस्य संकल्प प्रस्तुत करने की अनुमति लेंगे।

श्री राजेन्द्रपाल गौतमः माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से ध्यानाकर्षण की विषय वस्तु से संबंधित संकल्प प्रस्तुत करने के लिए सदन की अनुमति चाहता हूं।

माननीय अध्यक्षः यह प्रस्ताव सदन के सामने हैः

जो इसके पक्ष में हैं वे हाँ कहें,

जो इसके विरोध में हैं वे न कहें,

(सदस्यों के हाँ कहने पर)

हाँ पक्ष जी, हाँ पक्ष जीता,

प्रस्ताव पारित हुआ।

सदन द्वारा श्री राजेन्द्रपाल गौतम, माननीय सदस्य को संकल्प प्रस्तुत करने की अनुमति दी गई। अब माननीय सदस्य संकल्प प्रस्तुत करेंगे।

श्री राजेन्द्रपाल गौतमः माननीय अध्यक्ष जी, मैं एक संकल्प आज सदन के सामने प्रस्तुत कर रहा हूं और सदन के सदस्यों से निवेदन करता हूं कि इस संकल्प को पारित किया जाए। whereas residents of Dehi are suffering because of inflated water bills. There are around 27 lacs water connections out of which around 10.6 lacs customers have pending arrears (outstanding bills). Most of these consumers have stopped paying these water bills to DJB because they believe that their bills do not reflect their actual consumption of water. This problem has led to a situation where lacs of DJB consumers are not paying the bills and their successive bills are increasing on account of late payment charges and interest.

Whereas this problem is partly due to water meter readers not checking meter readings regularly, especially during COVID period.

Whereas Delhi Jal Board, at its board meeting on 13.6.2023 has deliberated and approved a 'One-time settlement scheme' formally

named as LPSC and Bill Recasting Scheme 2023 that would recast water bills based on average of minimum of 2 'OK' water meter readings. This scheme would bring relief to people of Delhi and unlock revenue for Delhi Jal Board.

Whereas this House fully supports this scheme and desires that it be implemented forthwith.

Whereas despite written directions by UD Minister and Finance Minister, the Principal Secretary (UD) and Principal Secretary (Finance) have refused to implement this pro-public scheme.

Whereas the officers have privately expressed inability to implement it because they have been threatened by 'higher ups' that they would be suspended or arrested by slapping false cases against them if they implemented this scheme.

Whereas it is shocking that the officers are openly and brazenly refusing to implement written orders of the Ministers, thus creating a grave constitutional crisis.

Whereas the House believes that the opposition party BJP, which exercises direct control over the officers of Delhi Government and also on Hon'ble LG, for narrow, short term and illegitimate political gains, is threatening the officers to prevent the popular government

of Delhi from implementing such a hugely necessary and pro-public scheme.

I propose that this House, while expressing its shock and dismay, requests Hon'ble LG to use his good Offices to get these officers implement this hugely pro-people scheme and to suspend them, if the officers do not implement it.

माननीय अध्यक्षः इस पर चर्चा के लिए सर्वप्रथम रोहित महरोलिया जी।

श्री रोहित कुमारः धन्यवाद माननीय अध्यक्ष जी जो आपने मुझे इस महत्वपूर्ण चर्चा में अपने विचार रखने का मौका दिया है। माननीय अध्यक्ष जी, दिल्ली के अंदर 27 लाख 65 हजार जल बोर्ड के उपभोक्ता हैं जिनमें से लगभग 10 लाख 50 हजार के आसपास के जो बिल हैं, उपभोक्ता हैं, वे अपने गलत बिल होने के कारण उन बिलों का भुगतान नहीं कर पा रहे हैं और बड़ी ही विकट स्थिति है। ये स्थिति उत्पन्न क्यूं हुई? ऐसा नहीं है कि महीने-दो महीने के अंदर ये साढ़े 10 लाख उपभोक्ताओं ने बिल देने से मना कर दिया। पिछले काफी समय से, मैं कहूंगा एक साजिश के तहत ये गलत बिल दिल्ली की जनता को भेजे गये। जिन लोगों के अभी तक बिल जीरो आ रहे थे अचानक से उनके 5-5, 7-7 हजार के बिल आने शुरू हो गये। इकट्ठे होते-होते उनके किसी का 50 हजार का बिल है, किसी का डेढ़ लाख का, किसी का दो लाख। मैं त्रिलोकपुरी का प्रतिनिधित्व

करता हूं सदन में, माननीय अध्यक्ष जी, 25 गज में रहने वाले परिवारों के बिल एक-एक लाख रुपये आ रहे हैं। ये बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है और जब इसके समाधान के लिए माननीय मुख्यमंत्री- अरविंद केजरीवाल जी ने, मंत्री जी ने, कैबिनेट ने ये प्रस्ताव भेजा है कि भई हम इसको सेटल करना चाहते हैं, एक बहुत ही शानदार सूझबूझ भरी स्कीम ये बनाई गई सरकार की तरफ से और पिछले, अभी हफ्ते- दस दिन पहले की बात नहीं है, एक साल पहले जनवरी में पटपड़गंज के अंदर एक यूजीआर के उद्घाटन के दौरान माननीय मुख्यमंत्री- अरविंद केजरीवाल जी ने जनता के बीच में, भरे मंच से ये औपचारिक एलान किया था कि हम इस प्रकार की एक स्कीम लेकर आ रहे हैं कि जिससे साढ़े दस लाख लोग लाभान्वित होंगे और साथ ही साथ जो उनको गलत बिल भेजे गये हैं उनका निपटारा भी किया जायेगा। और पिछले एक साल से लगातार बार-बार उन अधिकारियों को कहा जा रहा है और अधिकारी टाले जा रहे हैं। मुझे लगता है कि ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है और इस सदन का भी दुर्भाग्य है कि एक छोटी सी स्कीम, बेहतर होता कि इसकी जगह हम दिल्ली को वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने के लिए किसी महत्वपूर्ण, बहुत बड़ी कोई परियोजना के ऊपर चर्चा कर रहे होते। एक छोटी सी स्कीम की जो माननीय मुख्यमंत्री- अरविंद केजरीवाल जी या किसी भी प्रदेश का मंत्री भी अपने मौखिक तौर से भी आदेश देकर उसको लागू करवा सकता है, हम छोटी सी स्कीम लागू नहीं करवा पा रहे, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। इतनी शानदार स्कीम जिसके बारे में माननीय सदस्य, हमारे भारती जी ने विस्तार से बातें रखी हैं कि जो कोरोना के

दौरान या किसी और वजह से मीटर रीडिंग करने वाले घरों तक नहीं पहुंच पाये, जिन्होंने अपने दफ्तर में बैठकर, घर में बैठकर मनमाने तरीके से उन्होंने अनाप-शनाप रीडिंग लिख दी, उनको ठीक करने के लिए, अब उन्होंने बढ़ा-बढ़ाकर लिख दी, अब वो लोग कह रहे हैं नहीं भरेंगे। मेरे त्रिलोकपुरी में लोगों ने बोल दिया है कि हम फालतू, जो गलत बिल भेजे हैं उनको क्यों भरे। तो ये जिसमें सरकार को एक रुपया अपनी जेब से नहीं देना है बल्कि जो बिल ठीक हो जायेंगे उससे कुछ रेवेन्यू सरकार के पास आयेगा ही, जेब से तो कुछ जा नहीं रहा है। उसके बाद भी इस स्कीम को लागू करने को तैयार नहीं है। जब साफ शब्दों में कह दिया गया है कि ये कोई माफी योजना नहीं है, 'वन टाइम सेटलमेंट' है कि एक बार सेटलमेंट हो जाए फिर जीरो से स्टार्ट होकर फिर से लोग अपना बिल पे करना शुरू कर देंगे।

माननीय अध्यक्षः रोहित जी, कंकलूड करिये।

श्री रोहित कुमारः माननीय अध्यक्ष जी, अगर ये बिल अगर ये ठीक कर दिये जाते हैं तो लगभग 70 परसेंट लोगों के बिल जीरो हो जायेंगे अपने आप ही, इतनी शानदार स्कीम है कि 70 परसेंट लोगों के बिल जीरो हो जायेंगे और जिनका एक लाख का, डेढ़ लाख का बिल बना हुआ है, किसी को 5 हजार, 10 हजार, सीधी सी बात है कि जिस, एक साल पहले, दो साल पहले किसी ने अगर बिल अपना भरा है, उसके दो-तीन बिलों को देखकर या दो-तीन बिलों को उसके अनुसार बिल बनाकर कि भई ये नया बिल उनको पेश कर दिया जायेगा, सीधी सी साधारण सी बात है। माननीय अध्यक्ष जी,..

माननीय अध्यक्षः रोहित जी, कंकलूड करिये।

श्री रोहित कुमारः अरविंद केजरीवाल जी ने एलान कर दिया है सदन के अंदर ही ये भारतीय जनता पार्टी वाले..

माननीय अध्यक्षः रोहित जी, कंकलूड करिये अब।

श्री रोहित कुमारः सर, मैं दो मिनट और लूंगा, कुछ महत्वपूर्ण बात जोड़ना चाह रहा हूं।

माननीय अध्यक्षः नहीं, उतना समय नहीं है, प्लीज।

श्री रोहित कुमारः अध्यक्ष जी, एक मिनट के लिए। अरविंद केजरीवाल जी ने एलान कर दिया है कि आप चाहें कितना भी जोर लगा लें अपने केंद्र की एजेंसियों का दुरूपयोग करके, केंद्र की ताकतों का दुरूपयोग करके दिल्ली सरकार को अस्थिर करने का जो प्रयास किया जा रहा है, दिल्ली सरकार की योजनाओं को रोकने का काम किया जा रहा है, इनको किसी हालत में रूकने नहीं देंगे और चाहे फिर से हमें आंदोलन में क्यों न जाना पड़े। मैं माननीय अध्यक्ष जी याद दिलाना चाहूंगा कि दिल्ली के अंदर ही जब हम सरकार में नहीं थे तब भी हमने बहुत सारी चीजों को ठीक करवाया है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि 23 सितंबर, 2012 को अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली के जंतर मंतर पर उस समय जो कांग्रेस की सरकार थी, गलत बिल जो आते थे बिजली के उनकी होली जलाई थी और मेरा भी सौभाग्य रहा कि उस वक्त मैं अरविंद केजरीवाल जी के बाजू में खड़ा हुआ था, मैंने भी वहां पर उनके साथ बिलों की होली जलाई थी। तो

आज दिल्ली की जनता भी तैयार है, अरविंद केजरीवाल जी ने एलान कर दिया है कि ये गलत बिल है, साढ़े दस लाख बिल हैं, इनकी भी हम होली जलायेंगे, इसके लिए चाहे हमें आंदोलन में जाना पड़े, कैसे करना पड़े लेकिन हम इनको पास कराकर छोड़ेंगे इस स्कीम को और ताकि लोगों को न्याय मिल सके और जल बोर्ड को भी कुछ रेवेन्यू मिल सके इसके लिए मैं आग्रह करूंगा सदन से कि ये जो प्रस्ताव है इसको पास करा जाये और अधिकारियों को भी दबाव डाला जाये कि वो केंद्र के और एल.जी. साहब के दबाव में न आयें और जनता की सुने, जनता के हित में काम करें। माननीय अध्यक्ष जी, इस महत्वपूर्ण चर्चा में आपने बोलने का मुझे मौका दिया और इसका मैं पुरजोर समर्थन भी करता हूं कि जो माननीय सदस्य- सोमनाथ भारती जी ने ये चर्चा यहां पर शुरू की है कि इसको जल्द से जल्द इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए। बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।

माननीय अध्यक्षः श्री महेंद्र गोयल जी।

श्री महेंद्र गोयलः धन्यवाद अध्यक्ष जी जो आपने इस महत्वपूर्ण बिल पर जो संकल्प-पत्र राजेन्द्रपाल गौतम जी लेकर आयें, उस पर चर्चा के लिए समय दिया, आपका धन्यवाद। ये स्कीम अध्यक्ष जी 13 जून, 2023 को एक बोर्ड मीटिंग के अंदर लेकर आये थे कि एलपीएससी रिकास्टिंग बिल 2023 नामक एक मुश्त निपटान योजना है। पीछे का कितना भी बिल है, वो गलत है, सही है या कुछ भी है, उसके मीटर की रीडिंग 2 महीने की जो भी मिनिमम रीडिंग है उसके तहत ये बिलों को ठीक कर दिया जाए। बहुत अच्छी स्कीम थी। लोग चोरी नहीं

करना चाहते हैं, लोग नहीं चाहते हैं कि वो चोरी का पानी पीये, लोग ये चाहते हैं कि ईमानदारी के साथ में वो रहें और उनके ऊपर ईमानदारी का ठप्पा लगा रहे। लेकिन कुछ एजेंसियां लोगों को धक्के से मजबूर कर रही है चोर बनने के लिए।

मेरे क्षेत्र से आज मैं लोगों को लेकर आया, जो गैलरी के अंदर बैठे हैं, जिनके बिल गलत आये हुए हैं। बिल भी कितने-कितने, जहां पर 25-30 गज, 50 गज या 100 गज का मकान है वहां पर 2-2 लाख, 4-4 लाख, 5-5 लाख रुपये है। और बहुत से एरिये तो ऐसे हैं जिनके अंदर अल्टरनेट-डे के अंदर पानी जाता है, एक दिन छोड़कर एक दिन पानी जाता है और 2 घंटे के लिए पानी जाता है। मैं कहता हूं यूजीआर का पूरा का पूरा प्रेसर उन कालोंनियों में भी दे दे तब भी 20 हजार लीटर छोड़ 10 हजार लीटर भी पानी पूरा कर देंगे तब भी आपको बिल दे देंगे। जहां पर पानी नहीं जाता, इतने बिल कैसे आ रहे हैं, ये एक षड्यंत्र के तहत है। चूंकि सरकार बनाते वक्त अरविंद केजरीवाल ने एक ही संकल्प लिया था कि मैं अपने दिल्ली की जनता को 20 हजार लीटर पानी फ्री में दूंगा और उन्होंने दिया भी। 20 हजार नहीं दे सकें 10 हजार दिया, 10 हजार नहीं दे सकें 8 हजार दिया, लेकिन पानी को देने का उन्होंने प्रयास किया और पानी देकर रहे। लेकिन जनता ने भी अपना भरपूर प्यार दिया, लगातार 3-3 बार सरकार बनाई लेकिन केंद्र में बैठे हुए लोगों को ये हजम नहीं हो पाई, उनको एक ही बात होगी, केजरीवाल इनको पानी दे रहा है फ्री के अंदर, केजरीवाल इनको बिजली दे रहा है फ्री के अंदर। तो यहां पर समस्या

पैदा की जा रही है, उसी षड़यंत्र के तहत जो एक बोर्ड मीटिंग के फैसले के बावजूद ये आज तक लागू नहीं हुआ ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं इस सदन के माध्यम से उन लोगों को कहना चाहता हूं जो आततायी बने बैठे हैं, काम करो कुछ ऐसा, नेता विपक्ष से कहूंगा जरा गौर करना आप बहुत अच्छे आदमी हैं, बहुत अच्छी तरह से सुनते हैं, आपको सैल्यूट करता हूं, अपने आकाओं को जाकर बता देना:

"काम करो कुछ ऐसा कि लोग तुम्हारे लौटने का इंतजार करें
न करो अनर्थ कुछ ऐसा कि लोग तुम्हारे मिटने का इंतजार करें,
लोग तुम्हारे मिटने का इंतजार करें।"

ये जो लोगों के मुंह से आप पानी छीनने का काम कर रहे हैं, लोगों के बिलों के साथ में आप जो ज्यादती कर रहे हैं, और तो और बता देता हूं मैं अध्यक्ष जी, बहुत खुले तौर पर कह रहा हूं इस समय के अंदर ऐसी-ऐसी एजेंसियां लगा रखी हैं, नकली कापियां छपवाकर कि लोगों के घरों के अंदर बिलों को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। लोगों के घरों के अंदर एक-एक लाख रुपये का 50 हजार रुपये का, 60 हजार रुपये का बिल भेज दिया और लोगों से कहते हैं 5 हजार रुपये दे दे तेरा बिल निपटा देंगे, ये चोरी को बंद करवा दो। आप बहुत अच्छे आदमी हैं उन लोगों को समझा दो कि दिल्ली की जनता के साथ में ऐसा खिलवाड़ न करें।

माननीय अध्यक्ष: कंकल्यूड करिये महेन्द्र जी प्लीज।

श्री महेंद्र गोयलः कंकल्यूड तो समय कर देगा।

माननीय अध्यक्षः चलिए अब तो कंकल्यूड करिये।

श्री महेंद्र गोयलः और समय करेगा इस बात में भी कोई दो राय नहीं। ये तो ये भी बहुत अच्छी तरह जानते हैं 8 होते हुए भी 1 बैठे हैं 7-7 बाहर घूम रहे हैं। मैं तो कह रहा हूं बापू के बंदरों की तरह मतलब इसको बंदर शब्द यूज मत कर लेना बापू के वो 3 होते थे न उस तरह चाहे उनको भी कान पकड़कर बिठवा दिया करो कम से कम जनता की आवाज तो वो उठा लें।

माननीय अध्यक्षः चलिए महेन्द्र जी करिये अब, टॉपिक पर करिये प्लीज।

श्री महेंद्र गोयलः मैं बस एक ही बात कहता हूं जो इस प्रकार के षाड़यंत्र रचे जा रहे हैं, दिल्ली की इस जनता के साथ में जो खिलवाड़ हो रहे हैं इन बिलों का एकमुश्त निपटान जो योजना थी ये लागू होनी चाहिए और मैं तो इस सदन के माध्यम से अपने क्षेत्र की जनता को कहता हूं आज के बाद आप बिल मत भरना। मैं बहुत ऐसी बात कह रहा हूं जो मैं आज तक नहीं कहना चाहता था। आप बिल मत भरना, यदि कोई बिल लेने के लिए या आपका कोई पानी काटने के लिए आए तो महेन्द्र गोयल आपके साथ है, ये सदन आपके साथ में है। मैं आउंगा आपके पास में और कोई आदमी आपके यदि कनेक्शन काटने के लिए आता है तो उसको पकड़कर बिठा लेना, केस दर्ज होगा तो महेन्द्र गोयल के ऊपर होगा और मैं ओटूंगा उस चीज को।

माननीय अध्यक्षः चलिए धन्यवाद।

श्री महेंद्र गोयलः ये न हो की पूरे लोगों को सड़क के ऊपर उतरना पड़ जाए, इनकी नींद हराम करनी पड़ जाए मैं बस यही कहता हूं लोगों से शांति भी बनाए रखें, हो सकता है कि ये सदन के अंदर प्रस्ताव आया है, ये स्कीम आएगी और नहीं भी आई तो लोगों को सड़क पर उतरना पड़ेगा और इनकी नींद हराम करके रहेंगे जय हिन्द, जय भारत।

माननीय अध्यक्षः श्री विशेष रवि जी।

श्री विशेष रविः अध्यक्ष जी, नियम-54 के तहत माननीय सदस्य श्री सोमनाथ भारती जी के द्वारा जो ये चर्चा शुरु कराई गई है ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। अध्यक्ष जी, पिछले डेढ़ साल से, एक साल से लगभग जो है हमारे ऑफिस के अंदर लोग चक्कर काट रहे हैं अपने पानी के बिलों को लेकर और हर बार जब वो आते हैं तो हम उनको हर बार ये कह रहे हैं की भई अभी कुछ दिन में स्कीम आने वाली है, अभी कुछ दिन में स्कीम आने वाली है और लोग चक्कर काट-काटकर परेशान हो गये हैं लेकिन फिर भी हम उनको बड़ा पेशेंटली जो हैं हैंडल करते हैं और उनको समझाते हैं कि सरकार इस पर काम कर रही है और जल्दी ही जो है इस पर जो है योजना आने वाली है और जब पिछले दिनों माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह ऐलान किया और जब हमें यह जानकारी मिली कि बोर्ड ने भी इस स्कीम को पास कर दिया है जो वन टाइम सेटलमेंट स्कीम है पानी के बिलों

के ऊपर तो हमने फिर उसके बाद लोगों को बोलना शुरु कर दिया है कि भई अब बोर्ड ने इसको पास कर दिया है, अब बहुत जल्दी जो है ये स्कीम आपके बीच में आने वाली है और इतने दिन आपने वेट किया है तो कुछ दिन आप और वेट कर लें। तो वेट करते-करते जो है अब डेढ़ साल के आसपास हो गया है लेकिन स्कीम नहीं आई और अभी जैसे यहां पर जो हमारे वाइस चेयरमैन साहब हैं और कल भी और उससे पहले भी जब ये जानकारी दी गई कि यूडी सेक्रेटरी ने इस काम को जो उनको कहा गया था कि वो उसको कैबिनेट के आगे रखें, वो करने से मना कर दिया है। तो उसके बाद से और जब वो अखबारों में आया और न्यूज में आया तो उसके बाद से पब्लिक जो है वो और परेशान हो गई है। अब उनको समझाना मुश्किल हो रहा है और ये जो रोज-रोज की जो परेशानी जो हो रही है जो केन्द्र सरकार के द्वारा लाई जा रही है, केन्द्र सरकार नहीं चाहती की दिल्ली के अंदर कोई भी जो है योजना, कोई भी काम, कोई भी जनहित का कार्य पब्लिक के लिए किया जा सके और उसको वो रोकने में लगे हुए हैं। तो जो असली रास्ता है वो जिसको डिस्कस हम कर रहे हैं वो यही है कि अब हमें पब्लिक के बीच में जाना होगा, पब्लिक के बीच में जाकर जो है वो सब चीजें उनको बतानी पड़ेंगी और इस मुद्दे पर और अन्य मुद्दों पर जो है एक-एक करके जनता को तैयार करना पड़ेगा कि जनता जो है अपने आप फैसला करे कि कौन जो है गलत कर रहा है और कौन सही कर रहा है। तो मैं इस संकल्प के ऊपर जो है माननीय सदस्य ने जो नियम-54 में जो चर्चा शुरु की है मैं उसका समर्थन करता हूं और

जो भी सदन फैसला लेगा उसके अंदर हम जो है मिलकर काम करेंगे, धन्यवाद।

माननीय अध्यक्षः श्री साहनी जी।

श्री प्रलाद सिंह साहनीः आदरणीय अध्यक्ष जी, आपने मेरे को इस चर्चा में भाग लेने का मौका दिया मैं आपका धन्यवाद प्रकट करता हूं। एक बहुत अच्छी प्रपोजल है वन टाइम सेटलमेंट करने का, बहुत दिन से इलाके के लोगों को परेशानी थी, लाखों रुपये बिल आ जाते थे, एक ही बात हम लोगों को कहते थे कि थोड़े दिन में पालिसी आने वाली है आपका काम हो जाएगा आपको.. आज एकदम इस पालिसी को रोक देने से लोगों को काफी इलाके के अंदर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दूसरी इसके साथ एक चीज मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि जिसका मीटर खराब होता है लाखों रुपये उसके ऊपर ड्यूज लग जाते हैं कि उसका मीटर खराब है। जब वो मीटर की टैस्ट रिपोर्ट आती है तो जलबोर्ड डिपार्टमेंट के लोग कहते हैं टैस्ट करने के बाद आपका मीटर खराब है। जब मीटर खराब है तो पहले तो अक्सर ये हुआ करता था 1 साल का, 6 महीने का, 2 महीने की ऐवरेज ले ली जाती थी उस ऐवरेज के ऊपर बिल आता था। आज मेरे को समझ नहीं आ रहा जो भी जाता है जिसका मीटर खराब होता है उसको टाला जाता है, उसको कहते हैं कि इतने परसेंटेज का खराब है इतने पैसे आपसे कम किये जाएंगे मेरे को अभी तक यही नहीं पता कौन सी मशीन जलबोर्ड के पास है वो ये बताएगी कि इतने परसेंट

खराब है और इतने परसेंट खराब नहीं। मेरा आपसे इस हाउस के मार्फ्त अनुरोध है कि जितने भी बिल खराब हैं उनके बिल को रखा जाए और पिछली ऐवरेज 1 साल की, 2 साल की, 6 महीने की ऐवरेज पर उनको बिल बनाकर दिया जाए ताकि आसानी से उपभोक्ता अपना बिल पे कर सके, धन्यवाद।

माननीय अध्यक्षः श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी जी।

श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी (माननीय नेता, प्रतिपक्ष): आदरणीय अध्यक्ष महोदय, माननीय श्री सोमनाथ भारती जी के द्वारा वन टाइम सेटलमेंट स्कीम को लेकर कॉलिंग अटेंशन मोशन लाया गया है। आज मैं एक बात इस सदन में स्पष्ट करना चाहता हूं कि जून महीने में दिल्ली के ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर के द्वारा इसी तरह की घोषणा की गई थी, अब फिर घोषणा की गई है कि जिनके बिल ज्यादा आ गये हैं उनको माफी दी जाएगी। मैं आपके माध्यम से दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री जी को यह जानकारी दे रहा हूं कि दिल्ली की जनता में आपकी छवि खराब हो रही है। दिल्ली के लोगों का यह मानना है कि आम आदमी पार्टी की सरकार पहले तो लोगों के जो बिल हैं जो भेजे जाते हैं वो लाखों में भिजवाती है और उसके बाद फिर नाटक किया जाता है कि हम जो ज्यादा बिल आ गये हैं हम चाहते हैं कि माफी दी जाए। दिल्ली जलबोर्ड का चेयरमैन, दिल्ली की ऑनरेबल मिनिस्टर आतिशी जी हैं। कॉलिंग अटैंशन मोशन लाया गया है। आम आदमी पार्टी के ऑनरेबल एमएलऐज कहते हैं कि आफिसर्स गैलरी में अधिकारी नहीं हैं। इतने महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा हो रही है, कॉलिंग अटैंशन मोशन ऑनरेबल

सोमनाथ भारती के द्वारा लाया गया है लेकिन कंसर्न मिनिस्टर हाउस से गायब है। यदि आप इस पर चर्चा करवाना चाहते हैं तो कंसर्न मिनिस्टर को बुलाईये, वो चेयरमैन भी है। कम से कम इस आउस की गरिमा रहेगी या नहीं रहेगी और मैं आज आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर यहां बैठे हुए हैं कि मीडिया के द्वारा हमें मालूम हुआ है कि 2017-2018 के खातों की रिपोर्ट सीएजी ने सरकार को दे दी है। आखिर सरकार सीएजी की रिपोर्ट को इस सदन में क्यों नहीं पेश कर रही है जबकि 15 तारीख से सदन शुरु हो गया। ये जानकारी तो देनी पड़ेगी, बताएं कि 2016 से और अब तक दिल्ली जलबोर्ड के खातों की सीएजी के द्वारा जांच क्यों नहीं करवाई। आज बताएं ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर जब उनकी सरकार आई उससे पहले जलबोर्ड 600 करोड़ रुपये के मुनाफे में था आज 75 हजार करोड़ रुपये का घाटा कहिये या कर्जे के नीचे दबा हुआ है। तो आज मुख्यमंत्री जी बताएं कि आखिर क्या कारण है कि 75 हजार करोड़ रुपया आखिर दिल्ली के अंदर जो पीने के पानी की समस्या वैसी ही बनी हुई है, आप रेणुका बांध, ढ़िचाउ बांध से पानी ला नहीं पाए। डेढ़ सौ एमजीडी पानी आपको मुरादनगर से लाना था वो आप ला नहीं पाए। आपने ये वायदा भी किया था कि जब बरसात होगी तो जो यमुना का पानी बरसात में बह जाता है, हम किसानों की जमीन किराये पर लेकर बड़े-बड़े गड्ढ़े खोदकर उस पानी को स्टोर करके, ट्रीट करके दिल्ली के लोगों को उपलब्ध कराएंगे। आपने यह भी वायदा किया कि हम पल्ला और सोनिया विहार के अगल-बगल में रैनीवैल लगाकर दिल्ली के लोगों

की प्यास को बुझाएंगे। आपने ये वायदा भी अनेकों बार किया कि हम दिल्ली के लोगों को 24 घंटे क्लीन वाटर उपलब्ध कराएंगे। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं कि जलबोर्ड ने लगभग 7411 सैंपल्स लोगों के घरों से उठाये 2508 सैंपल पीने के पानी के फेल हो गये और इसी पानी को पीकर दिल्ली के लोगों की किडनी खराब हो रही है, लीवर खराब हो रहे हैं, पेट खराब हो रहे हैं आखिर दिल्ली के ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर बताएं कि ये जो सैंपल्स फेल हुए हैं जो आप गंदा पानी दिल्ली के लोगों को पिला रहे थे, आखिर किसकी जिम्मेवारी है, इस सदन में ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर को बताना चाहिए।

माननीय अध्यक्षः बिधूड़ी जी चर्चा किसी और विषय पर थी आप..

....व्यवधान....

श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी (नेता प्रतिपक्ष): नहीं नहीं।

माननीय अध्यक्षः नहीं मेरी बात सुन लीजिए, मैं शांति से सुन रहा हूं बहुत देर से।

श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी (नेता प्रतिपक्ष): ये उसी से कनेक्टेड है,

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः भई आप बोल लीजिए फिर मेरी आवश्यकता नहीं है, विषय, चर्चा मैं सुन रहा हूं आप जबसे बोल रहे हैं 5 मिनट सुना है। विषय जो था चर्चा का उस विषय से आप डायवर्ट हो रहे हैं कृपया मेरी प्रार्थना है विषय पर आईये नहीं तो मुझे मजबूरन बिठाना पड़ेगा। विषय जो था उस विषय पर आपको जो कुछ बोलना है बोलिए।

श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी (माननीय नेता, प्रतिपक्ष): आदरणीय अध्यक्ष जी, ये आरोप लगाया जा रहा है अधिकारी सुनते नहीं, अधिकारी किसके मातहत हैं, ऑनरेबल मिनिस्टर के मातहत हैं, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर के मातहत हैं।

....व्यवधान....

माननीय अध्यक्षः हां बोलिए किसके मातहत हैं।

श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी (माननीय नेता, प्रतिपक्ष): जलबोर्ड का चेयरमैन।

श्रीमती राखी बिरला: अध्यक्ष जी ये निकलवाया जाए, नहीं ये निकलवाया जाए।

....व्यवधान....

माननीय अध्यक्षः अभी उत्तर देंगे न सौरभ जी उत्तर देंगे भई,

....व्यवधान....

माननीय अध्यक्षः देखिये मेरी बात सुनिये ऐसे नहीं चलेगा, सौरभ जी उत्तर देंगे न इसके बाद सौरभ जी बोलेंगे न।

श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी (माननीय नेता, प्रतिपक्ष): मैं कभी जब आम आदमी पार्टी के ऑनरेबल एमएलऐज बोलते हैं मैं कभी डिस्टर्ब करता नहीं।

श्रीमती राखी बिरलाः आप झूठ भी बोलते हैं।

माननीय अध्यक्षः चलिए आप बोलिए आप बोलिए।

श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी (माननीय नेता, प्रतिपक्ष): नहीं अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो कार्यवाही से निकाल दिया जाए। जो सजा ऑनरेबल स्पीकर मेरे लिए तय करना चाहें कर दें मैं उस सजा को स्वीकार करूंगा।

माननीय अध्यक्षः चलिए शुरु करिये जल्दी शुरु करिये प्लीज।

श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी (माननीय नेता, प्रतिपक्ष): लेकिन कम से कम लीडर आफ अपोजीशन की आवाज दबाने का प्रयास मत करों। अन्य विधानसभाओं की जो परंपरा रही है, परंपरा यह है।..

माननीय अध्यक्षः परंपरा तो यह है कि एलजी के भाषण के दौरान कोई बोलता नहीं है अगर परंपरा पर जाएंगे। एलजी के भाषण के दौरान कोई बोलता नहीं है।

श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी (माननीय नेता, प्रतिपक्ष): नहीं मैंने तो टोका ही नहीं।

माननीय अध्यक्षः हां, परंपरा तो यह रही है।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः आप शांत रहिये प्लीज, चलिए।

श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी (माननीय नेता, प्रतिपक्ष): मैं विषय पर आ जाता हूं।

माननीय अध्यक्षः हां विषय पर आईये।

श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी (माननीय नेता, प्रतिपक्ष): आप कह रहे हैं विषय पर आ जाईये। अरे दिल्ली जलबोर्ड का चेयरमैन हमारी ऑनरेबल मिनिस्टर हैं, अरे वाइस चेयरमैन आदरणीय सोमनाथ भारती जी हमारे क्रांतिकारी नेता, अरे आपके अधिकारी नहीं सुन रहे मैं इस हाउस में कहता हूं। एक महीने के लिए रामवीर सिंह बिधूड़ी को सरकार के हवाले कर दीजिए मैं बताउंगा की अधिकारी सुनते हैं या नहीं सुनते हैं, कर दीजिए, कर दीजिए एक महीने के लिए कर दीजिए मैं देखता हूं क्योंकि आज अधिकारी इसलिए नहीं सुनते हैं कि आप अधिकारियों को गलत काम करने के लिए निर्देश देते हो, निर्देश गलत आप देते हो।

....व्यवधान....

माननीय अध्यक्षः चलिए हो गया।

श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी (माननीय नेता, प्रतिपक्ष):कहां अभी,

....व्यवधान....

माननीय अध्यक्षः आप चलिए फिर करिये पूरा करिये, पूरा करिये।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः तो सौरभ जी उत्तर देंगे, सौरभ जी उत्तर देंगे। सौरभ जी पूरा उत्तर देंगे चिंता मत करिये, पूरा उत्तर देंगे सौरभ जी। हां, चलिए-चलिए।

श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी (माननीय नेता, प्रतिपक्ष): मैं अब जब अधिकारी ऑनरेबल मिनिस्टर के मातहत हैं, जलबोर्ड में चेयरमैन मिनिस्टर हैं। डिप्टी चेयरमैन आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ विधायक, पूर्व मंत्री आदरणीय सोमनाथ भारती जी हैं, जलबोर्ड में दिल्ली असेम्बली की तरफ से और दो मेंबर हैं, नगर निगम की ओर से आम आदमी पार्टी के जो काउंसिलर हैं वो मेंबर हैं। अरे इतना सब कुछ दे दिया आपको और उसके बाद रोज रोना धोना लगा रहता है। ये रोना धोना बंद करिये, मैं अपनी बात को समाप्त कर रहा हूं। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब जनता ये सुनना नहीं चाहती है। इसका नुकसान आपको होगा, ये जो रोज का जो नाटक है हम ये करना चाहते हैं एलजी साहब नहीं करने देना चाहते, अधिकारी नहीं करने देना चाहते, मैं आज आपको कह रहा हूं इस हाउस में क्यूंकि मेरा 53-54 साल का राजनीतिक जीवन है इसका आपको नुकसान होगा और जब विधान सभा का चुनाव आयेगा, अभी लोकसभा का चुनाव आ रहा है विधान सभा का जब चुनाव आयेगा तो लोग ये कहेंगे कि अगर इस सरकार के चलते यही झगड़े होते हैं और दिल्ली की जनता के हित में कोई काम नहीं हो रहा है

तो इसलिये केंद्र में भी मोदी जी की सरकार आ गयी है, आपने ये बात..

....व्यवधान.....

श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी (माननीय नेता, प्रतिपक्ष): अरे ये तो मुख्यमंत्री ने बोला है, तो दिल्ली की जनता ये कहेगी कि झगड़ा समाप्त करने के लिये दिल्ली विधान सभा में भी भाजपा की सरकार लाओ जिससे कि दिल्ली को वर्ल्ड क्लास सिटी बनाया जा सके। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आदरणीय अध्यक्ष जी बहुत बहुत आपका धन्यवाद करता हूं और सरकार से आग्रह करता हूं कि आप अधिकारियों से काम लेना सीखिये, यदि आपको नहीं काम लेना आता है तो फिर मेरे से ट्रेनिंग ले लीजिये मैं आपको ट्रेनिंग दे दूंगा इसके बारे में और परफैक्ट होगा, बहुत बहुत धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष: माननीय मंत्री श्री सौरभ भारद्वाज जी।

श्री सौरभ भारद्वाज (माननीय जलमंत्री): अध्यक्ष जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपने मुझे मौका दिया। आज रामवीर सिंह बिधूड़ी जी ने थोड़ा इमोशनल हो के जो चुनाव की पिच इनकी 8 महीने बाद होनी थी वो इन्होंने आज ही बता दी। आज इन्होंने भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रेटजी जो है इस हाउस में सबको बता दी। वो स्ट्रेटजी क्या बताई इन्होंने आप सुनिये, इनका जैसे बिल्ली जो है न वो छींका देखती रहती है कि ये फूटेगा, कभी गिरेगा, मुझे मिलेगा, भारतीय जनता पार्टी पिछले 27 सालों से दिल्ली के अंदर 1997 के बाद से छींका देख रही है कि

ये अपने आप फूटेगा, ये गिरेगा, मक्खन हमें मिलेगा। बिधूड़ी जी, नहीं मिलेगा। आपको नहीं मिलेगा। और उसका कारण ये है कि आप लोगों ने जनता के लिये कभी कुछ नहीं किया। कल मुख्यमंत्री जी ने भी अपने भाषण में बताया, लोग सोचते हैं कि अच्छा काम हो रहा है इसमें चलो कुछ अच्छा कर लें। आपकी सरकार ने हमेशा जनता के विरोध में काम किया। आपने अस्पतालों के काम रोके, आपने मोहल्ला क्लिनिक के काम रोके, आपने बुजुर्गों की पेंशन रोकी, आपने दिल्ली जलबोर्ड के काम रोके, जनता सब देख रही है। आपको लग रहा है कि जनता को नहीं पता, ये 70 विधायक हैं ये सब बताते हैं जनता को, जनता को सब पता है। अब बात आती है इसकी वन टाईम सेटलमेंट स्कीम की। आपने सब बारे में बात की मगर आपने ये नहीं कहा कि आप चाहते हैं वन टाईम सेटलमेंट स्कीम आये या आप नहीं चाहते हैं, आपने इस विषय पे नहीं बताया। और उसका कारण क्या है, उसका कारण भी आप समझिये क्योंकि अगर आपके पास थोड़ा समय होता होगा और आप अपनी विधान सभा के कार्यालय में बैठते होंगे तो अध्यक्ष जी सौ प्रतिशत मैं बता सकता हूं क्यूंकि बदरपुर के लोगों से मैं भी मिलता रहता हूं, सौ प्रतिशत ये है कि लोग आते होंगे और कहते होंगे बिधूड़ी जी वन टाईम सेटलमेंट स्कीम के बारे में केजरीवाल जी बता चुके हैं, सिसोदिया जी बता चुके हैं, वो कब आयेगी। और ये कहते होंगे मैं हंड्रेड परसेंट कह रहा हूं ये जनता को कहते होंगे हां आने वाली है, ये कहते होंगे। नहीं तो ये आज अपने ट्विटर पे, फेसबुक पे जनता को कह दें कि भई आज मैं दिल्ली विधान सभा में

वन टाईम सेटलमेंट स्कीम का विरोध करके आया हूं, वो स्कीम हम नहीं आने देंगे, ये बात कहें न, छुप के क्यों घूम रहे हैं, इनको ये बात कहनी चाहिये अपने ट्विटर पे, फेसबुक पे।

....व्यवधान....

माननीय अध्यक्षः बिधूड़ी जी आपने माननीय मंत्री जी को..

....व्यवधान....

श्री सौरभ भारद्वाज (माननीय जल मंत्री): अध्यक्ष जी चलिये ये बहुत अच्छा हो गया कि राजेन्द्र पाल गौतम जी अब जो रेज्योल्यूशन लाये हैं हाउस में उसके अंदर जो है जब हम वोटिंग करायें मेरा मानना ये है कि वोट की काउंट करा लें जिसके अंदर वो डिविजन होता है ताकि रामवीर सिंह बिधूड़ी जी खड़े होते हैं या बैठते हैं वो दिल्ली की जनता को पता चल जाये। वरना क्या है हां और न में कई बार पता नहीं चलता कौन साथ है और कौन विरोध में है। तो ये हमारे लिये बहुत जरूरी रहेगा। अब अध्यक्ष जी, इस वन टाईम सेटलमेंट स्कीम के उपर आते हैं। ये स्कीम इसलिये जरूरी थी क्योंकि दिल्ली के अंदर पिछले कई वर्ष से एक समस्या आई कि मीटर रीडरों ने समय पे या तो मीटर की रीडिंग नहीं ली, रीडिंग ली तो समय पे बिल नहीं दिया, और ये समस्या कोरोना के दौरान और ज्यादा बढ़ गयी क्योंकि कोरोना के दौरान दिल्ली जलबोर्ड को ये कहा गया था कि आपके मीटर रीडर जो हैं लोगों के घर नहीं जायेंगे, लॉक डाउन लगे हुए थे। तो ज्यादातर जगहों पे या तो मीटर स्टाप की रीडिंग दी गयी या एवरेज की रीडिंग

दी गयी या रीडिंग जो है दिल्ली जल बोर्ड के मीटर रीडर्स बनाते गये मगर लोगों को समय पे उनके बिल नहीं दिये गये। तो लोगों को ऐसा लगा कि हमारा बिल नहीं आ रहा इसका मतलब हमारा जीरो बिल है। हम 20 हजार लीटर के अंदर हैं इसलिये उन्होंने बिल जो है नहीं दिया। और जब अचानक उनको बढ़े हुए बिल भेजे गये तो लोगों को लगा कि भई हमारी तो इतनी कंजम्पशन है ही नहीं, हम इतना बिल कैसे दे दें। और फिर लोगों ने इस वजह से वो बिल देने बंद कर दिये। जब मैं दिल्ली जल बोर्ड का वाईस चेयरमैन था तो इसके बारे में कई बार चर्चा हुई, मनीष जी हमारे चेयरमैन थे, कई बार उनके साथ भी जो है बोर्ड में चर्चा हुई, पहली बार ये चर्चा जो है दिल्ली जल बोर्ड की बोर्ड की मीटिंग में 2023 जनवरी में आई जब मनीष जी ने इसके बारे में प्रेस काफ्रेंस करके भी कहा कि हम जल्द जो है इस स्कीम को ला रहे हैं। सर, इसके अंदर मोटे तौर पे ये था कि दिल्ली के अंदर करीब 26 लाख 68 हजार कंज्यूमर्स हैं, इसमें से करीब 10 लाख 68 हजार कंज्यूमर्स ऐसे हैं जिनके एरियर्स पेंडिंग हैं और उनको ऐसा लगता है कि उनको ये जो बिल दिया गया है उनकी खपत के अनुसार नहीं है इसीलिये उन्होंने बिल देना बंद कर दिया, अब एक डेडलॉक की स्थिति है कि दिल्ली जलबोर्ड मानता है कि हमें हजारों करोड़ रूपया जो है वो कंज्यूमर्स से लेना है, वो आ नहीं रहा है, वो सिर्फ वो बैठे हैं। हर महीने दिल्ली जल बोर्ड उसके उपर लेट पेमेंट चार्जिज लगा देता है और उसके उपर इंट्रस्ट लगा देता है और बढ़ जाता है। कंज्यूमर उसको नहीं दे रहा है, दिल्ली जलबोर्ड सोच रहा है वो आ जायेगा। तो एक

डेडलॉक की स्थिति है उसके अंदर हमने जो स्कीम लाये हैं उसके अंदर हमने ये कहा है कि उसी कंज्यूमर की कोई ऐसी रीडिंग जो सही रीडिंग थी उस रीडिंग के हिसाब से उसके अनपेड पीरियड के अंदर हम उसका बिल रिकास्ट कर दें। उसको एक्स्ट्रापोलेट करके, उसको दोबारा कैलकुलेट करके उसको हम एक वन टाईम ऑफर दे दें, और वो ऑफर इस तरह से रहेगा अध्यक्ष जी कि मान लीजिये उसका बिल है 2 लाख रूपये, मगर हमने उसकी जो एवरेज खपत देखी उसके हिसाब से अगर हमने उसका बिल निकाला तो वो बना मान लीजिये अध्यक्ष जी 12 हजार रूपये तो हम उसको कहेंगे कि भई आपको दिल्ली जल बोर्ड की तरफ से 12 हजार रूपये का ऑफर दिया जा रहा है अगर आप ये 12 हजार रूपये दे देते हैं तो आपका सारा बकाया माफ है, जीरो से जो है आपकी दोबारा शुरूआत करेंगे और जो है मुझे लगता है अध्यक्ष जी, इसके अंदर जो लाखों कंज्यूमर हैं ये कोई छोटी वैल्यू नहीं है अध्यक्ष जी, करीब साढे 26 लाख में से साढे 10 लाख लोग नहीं दे रहे मतलब करीब 40 परसेंट कंज्यूमर दिल्ली जलबोर्ड का बिल नहीं दे रहा है इस डेडलॉक को तोड़ने की जरूरत है और सरकार बहुत ही प्रोग्रेसिव, रैशनल, ऑटोमेटिड स्कीम लाई है क्योंकि अध्यक्ष जी, जिस तरीके से दिल्ली जल बोर्ड के अंदर इन समस्याओं का निवारण किया जाता है वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है सबका। वो हमने डेटा निकलवाया है अध्यक्ष जी। जब मैं वाईस चेयरमैन था दिल्ली जलबोर्ड का तो जो डेटा निकाला उस समय वो ये पूछा मैंने कि भई पिछले आठ महीने में आपने कितने बिलों को जो है ठीक करा है। तो दिल्ली

जलबोर्ड का जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट का डेटा था कि पिछले आठ महीनों में उन्होंने करीब 8 हजार बिलों को ठीक किया। आठ महीने में 8 हजार बिल ठीक हुए और 42 रेवेन्यू ऑफिसिस हैं जैडआरओ के। तो उसके हिसाब से अगर हम उसको भाग करें तो एक दिन में एक जैडआरओ ऑफिस में .79 बिल ठीक होते हैं मतलब एक बिल भी एक जैडआरओ ऑफिस में प्रतिदिन ठीक नहीं होता। अगर इस हिसाब से इन दस, साढे दस लाख लोगों को आप माने कि इन सबका निवारण किया जाये अध्यक्ष जी इसके अंदर 80 वर्ष लगेंगे। क्या 80 वर्ष तक हम इंतजार कर सकते हैं, क्या 80 वर्ष तक इस डेडलॉक को बनाया जा सकता है और ये जबर्दस्ती जो है जलबोर्ड के खातों के अंदर ये पैसा दिखाते रहते हैं। उससे सिर्फ जो है सिर्फ नुकसान है, इसलिये ये वन टाईम पॉलिसी जो है हम लेके आये और ये दिल्ली जलबोर्ड की बोर्ड मीटिंग के अंदर पास हुई। ये बात है 13 जून 2023 की और फिर मुख्यमंत्री जी लगातार जो है इसके बारे में हमसे चर्चा करते रहे, इसके फॉर्मूले के उपर पूरा चर्चा हुआ, थ्रेडबेयर इसकी चर्चा हुई और फिर ये कहा गया कि इसको जो है कैबिनेट के अंदर लाना जरूरी है, अफसरों ने ही कहा कि इसको कैबिनेट में लाना जरूरी है और कैबिनेट में ले आयेंगे तो इस बिल को हम इंप्लीमेंट कर देंगे और उस कैबिनेट को लाने के लिये कई बार मौखिक और लिखित आदेश जो है अफसरों को दिये जा चुके हैं मगर उन आदेशों के बावजूद भी कुछ अफसर जो हैं इसको जो है कैबिनेट में लाने के लिये तैयार नहीं हैं। और मुझे लगता है कि उसका मुख्य कारण ये है, मैं ये नहीं कहूंगा

कि अफसर जो है उसका कोई फायदा या नुकसान है इस पॉलिसी को ला के या नहीं ला के। पानी की बात हो रही है, पानी के बारे में एक बहुत पुराना गाना है 'पानी रे पानी तेरा रंग कैसा जिसमें मिला दें बने उस जैसा' अफसरों का भी ऐसा ही है अध्यक्ष जी। ब्यूरोक्रेसी और अफसर भी इसी तरीके से हैं वो पानी की तरह हैं उनका न कोई रंग है, न कोई उनका आकार है, जिस आकार के बर्तन में डाल दो वो उसी आकार को ले लेते हैं और जो रंग उनमें मिला दो वो रंग ले लिया। आजकल जो है उनके उपर भारतीय जनता पार्टी का रंग मिला हुआ है, ये तो सबको मालूम है। इसलिये वो अफसर क्या करें, उनको वही करना पड़ रहा है जो रामवीर बिधूड़ी जी की जो पार्टी है वो उनको बोल रहे हैं। वर्ना ऐसा कैसे हो सकता है कि पब्लिक के लिये एक पॉलिसी लाई जा रही है, इस तरीके की पॉलिसिज़ पहले भी लाई गयी हैं, बकायदा वो इंप्लीमेंट हुई हैं। हर राज्य की सरकार इस तरीके की पॉलिसिज़ अपने राज्यों में लाती है मगर इस पॉलिसी को जो है दिल्ली के अंदर रोका जा रहा है। मैं ये मानता हूं कि ये जो पॉलिसी है सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के केन्द्र सरकार के दबाव के अंदर अफसर इसको नहीं ला रहे हैं और हम लोग इसके लिये पूरी तरीके से तैयार हैं कि इसके उपर सड़क पर, विधान सभा में और गली गली में इस लड़ाई को हम लोग लड़ेंगे और इस चीज को हम लोग सारी दिल्ली के अंदर लेके जायेंगे कि कैसे एक पॉलिसी जो हम ला रहे हैं उसको भारतीय जनता पार्टी अपने एलजी की वजह से, भारतीय जनता पार्टी अपनी केन्द्र सरकार की वजह से उसको अफसरों के उपर

दबाव बना के ये रोक रहे हैं। बिधूड़ी जी ने दो तीन बातें बोली कि जलबोर्ड की अध्यक्षा यहां क्यों नहीं हैं? मैं उनको बताउं ये जो कैबिनेट प्रपोजल ला रहे हैं वो यूडी डिपार्टमेंट का प्रपोजल है, मेरे विभाग का प्रपोजल है, मैं उस विभाग का एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्टर हूं तो इसलिये मैं इस चर्चा के अंदर मौजूद हूं और जब ये पॉलिसी पास हुई तब भी मैं ही दिल्ली जलबोर्ड का चेयरमैन हुआ करता था जून-जुलाई 2023 के अंदर, उस वक्त वाईस चेयरमैन सोमनाथ भारती जी थे, वो भी इस वक्त इस सदन के अंदर मौजूद हैं ताकि इस पॉलिसी से संबंधित कोई भी सवाल रामवीर बिधूड़ी जी का हो तो हम इनके सवाल का जवाब दे सकें, कोई और सवाल भी हो इनके पास तो वो इस सदन के बाद मुझसे मिल लें मैं इनके सवालों का जवाब दूंगा। हम इसके अंदर पूरी ट्रासंपेरेंसी रखना चाहते हैं और अध्यक्ष जी मजे की बात ये है कि अगर हम इस पॉलिसी को इंप्लीमेंट कर देंगे, हमने ये देखा कि लोगों के जो पुराने बिल हैं किसी का लाख है, किसी का 50 हजार है, किसी का 2 लाख है वो अनाप-शनाप एरियर्स, इंट्रस्ट, लेट पेमेंट चार्जिज़ की वजह से बढ़े हुए हैं। मगर अगर हम उनकी पुरानी खपत देखें तो उनकी खपत मैं आपको एक उदाहरण के तौर पे बताना चाहता हूं अध्यक्ष जी, जैसे मान लीजिये हमारे पास किसी कंज्यूमर की 5 रीडिंग हैं और वो 5 रीडिंग इस तरीके से है कि उसने 18 यूनिट इस्तेमाल किया, 19 यूनिट इस्तेमाल किया, 20 यूनिट इस्तेमाल किया, 21 यूनिट इस्तेमाल किया और 150 यूनिट इस्तेमाल किया तो कुछ महीनों में तो उसकी यूनिट ऐसे दिखा रहा है कि 18 यूनिट, 19 यूनिट, 20 यूनिट,

21 यूनिट और एक महीने में उसकी खपत दिखा रहा है 150 यूनिट तो मैं ये समझता हूं कि अगर इस तरीके की किसी की रीडिंग है तो औसतन कोई भी आदमी मान लेगा कि इस आदमी की, इस कंज्यूमर की रीडिंग लगभग 19-20 यूनिट के आसपास होगा, तो उसी तरीके से इस पूरी की पूरी पॉलिसी को डिजाईन किया गया है, पूरी तरीके से ऑटोमेट इसलिये किये गया है अध्यक्ष जी क्योंकि हर आदमी जैडआरओ ऑफिस जाये और 80 साल लेके हम उसका निवारण करें, ये हो नहीं सकता। आजकल इस तरीके के बहुत सारे कम्प्यूटराईज साफ्टवेयर अवेलेबल हैं, उसके अंदर हमने इन फॉर्मूलाज़ को डाल के बहुत रैशनल और बहुत सही स्कीम जो है हम लोग दिल्ली के लिये लेके आये हैं और मेरी पूरी इस विधान सभा से ये निवेदन रहेगा कि आप सब लोग अपनी तरफ से इस स्कीम का समर्थन कीजिये क्योंकि ये स्कीम बहुत ज्यादा रैशनल है और सबके लिये जो है ये एक ऐसा मौका लेके आयेगी जिसके अंदर वो सब लोग अपनी जीरो से जो है शुरूआत कर सकते हैं। एक और खास चीज अध्यक्ष जी मैं इस स्कीम के बारे में बता दूं अब तक जितनी भी स्कीमें दिल्ली सरकार लाई थी वो स्कीमें सब उनके लिये थी जिनके पास एक ऑपरेटिड मीटर है यानि कि उनका मीटर चल रहा है। तो इस कारण से करीब दो लाख कंज्यूमर हमारे अध्यक्ष जी दिल्ली के अंदर थे जिन्होंने 2012 से अब तक यानि कि पिछले पूरे 12 साल के अंदर न कभी किसी स्कीम का फायदा उठाया, न उन्होंने आज तक भी कोई बिल पे किया। और ये भी माना जा सकता है कि इनके अंदर अधिकतर लोग ऐसे होंगे जिनके शायद

कभी बिल ही जनरेट नहीं हुए या उनको कभी बिल ही नहीं मिले। ऐसे भी लोग होंगे उसके अंदर बहुत सारे जिनके यहां मीटर ही नहीं लगे हुए, उनके सिर्फ नंबर अलॉटिड हैं, उनके यहां वाटर कनेक्शन अलॉटिड हैं, उनके यहां बिल जनरेट होता है मगर उनके यहां मीटर नहीं लगा हुआ। तो इस बार हम लोग जो स्कीम ला रहे हैं इसके अंदर हम उन दो लाख लोगों को भी एक मौका देना चाहते हैं कि हम उनको एक वन टाईम ऑफर दें और अगर उन दो लाख लोगों में से अध्यक्ष जी 20 हजार लोग भी, 10 परसेंट लोग भी अपना बिल पे कर देते हैं, मान लीजिये उसका 4 लाख बिल था हमारा ऑफर ये है कि उसको हम 20 हजार रूपये के अंदर ऑफर देंगे कि आप इसको पे कीजिये, अपना जीरो कर लीजिये। तो अगर 20 हजार लोग भी इसके लिये तैयार हो गये तो हम 20 हजार नये कंज्यूमर्स जलबोर्ड की रेवेन्यू साईकल के अंदर ला पायेंगे जिसके अंदर आगे जलबोर्ड को भी जो है रेवेन्यू का फायदा होगा। मैं दोबारा से सभी हाउस के मेंबर्स को ये निवेदन करूंगा कि इस पॉलिसी को जो है आप सर्वसम्मति से इस रेज्योल्यूशन का जो आप साथ दें, बहुत बहुत धन्यवाद।

माननीय अध्यक्षः माननीय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी चर्चा का उत्तर देंगे।

माननीय मुख्यमंत्री (श्री अरविंद केजरीवाल): अध्यक्ष महोदय, ये बिल्कुल सही बात है कि हमारी सरकार है और हमारी ही सरकार की एक पोलिसी लागू नहीं हो रही और उस पोलिसी को लागू कराने के लिए आज यहां पर चर्चा हो रही है। दिल्ली के अंदर लोगों के

गलत बिल आ रहे हैं, उन गलत बिलों को ठीक कराने के लिए आज सत्तापक्ष कह रहा है कि बिल ठीक होने चाहिए और विरोधी पक्ष कह रहा है कि बिल ठीक नहीं होने चाहिए। ये एक बड़ी विसंगति है दिल्ली को लेकर। दिल्ली कहने को आधा राज्य है, मेरे को तो लगता है 5 प्रसैंट भी राज्य नहीं है। अगर ये फुल स्टेट होता, किसी ऑफिसर की हिम्मत नहीं थी कि मंत्री और मुख्यमंत्री द्वारा दिये गए आदेशों की अवहेलना करके वो दो मिनट के अंदर अपनी पोस्ट के उपर रह जाता, सस्पैंड कर दिया जाता वो सीधा। आज ये चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि दिल्ली एक बहुत गंदी और नीच राजनीति का शिकार है। आज ये चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि दिल्ली एक पूर्ण राज्य नहीं है और इसके बदोलत रियल पावर जो है वो केंद्र सरकार के पास है, केंद्र सरकार दूसरी पार्टी की है और वो दूसरी पार्टी नहीं चाहती कि दिल्ली के अंदर चुनी हुई सरकार अपना काम कर सके। अभी मेरे भाई सौरभ भारद्वाज जी ने बहुत विस्तार से इस पूरी स्कीम के बारे में बताया, मैं इसको संक्षेप में बताना चाहूंगा कि दिल्ली के अंदर लगभग 27 लाख कंज्यूमर है मोटा-मोटा इन 27 लाख में से लगभग साढ़े 10 लाख कंज्यूमर ऐसे हैं, यानि की 40 प्रसैंट कंज्यूमर्स ऑफ डेहली वो ऐसे हैं जो अपना बिल नहीं भर रहे। वो बिल क्यों नहीं भर रहे? क्योंकि उनको लगता है कि उनके बिल गलत आए हैं, उनके बिल बढ़-चढ के आए हैं और उनके बिल सही नहीं है। इसलिए वो अपने बिल नहीं भर रहे। ये कोई छोटी-मोटी वो नहीं है, 40 परसैंट दिल्ली के लोग, डोमेस्टिक कंज्यूमरस अगर बिल नहीं भर रहे तो इसकी किसी भी

जिम्मेदार सरकार की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो इसके बारे में कोई पोलिसी डिसीजन लेकर आए। तो एक तरफ सारे कंज्यूमरस दुखी है। कंज्यूमर चक्कर पे चक्कर लगाते हैं अपने बिल ठीक कराने के लिए, चक्कर पे चक्कर लगाते हैं, दलालों के चक्कर लगा रहे हैं, रिश्वतखोरी चल रही है, हर किस्म का गलत काम चल रहा है इस वजह से कि इतने सारे बिल पेंडिंग पड़े हुए हैं, इतने सारे बिल गलत हैं। ये बिल गलत क्यों है? इसके बहुत सारे कारण है। लेकिन एक बहुत बड़ा कारण बिल गलत आने का ये कोविड के दौरान जब बहुत महीनों तक मीटर रीडर मीटर रीडिंग लेने के लिए नहीं गए, कई-कई महीनों तक बिल जैनरेट नहीं हुए, कईयों के बिल जनरेट हुए तो एवरेज के ऊपर जेनरेट कर दिए गए, किसी की फर्जी रीडिंग लिख दी गई। कोविड के दौरान इतने लार्ज स्केल के ऊपर प्रोब्लम हुई कि आज 40 प्रसैंट दिल्ली जो है वो गलत बिलों इन्फलेटिड बिलस का शिकार है। हमारी आम आदमी की सरकार है, जनता की सरकार है, हम जनता की भलाई देखते हैं, जैसे अभी और भी कईयों ने बताया कि रोज अगर आप एमएलए दफ्तर में बैठें तो सुबह से शाम तक बिल ठीक कराने वालों का तांता लगा हुआ है, तांता लगा हुआ है। इसे कैसे नजरअंदाज किया जा सकता है। इन लोगों ने आज तक ऐसे जनता की समस्याओं को नजरअंदाज किया और जनता की समस्याओं पर खुशी मनाई इसलिए आज इनका ये हाल है कि कभी 3 सीट आती है इनकी, कभी 8 सीट आती है इनकी। अब हम जनता की समस्याओं का समाधान, इन समस्याओं का समाधान करने के लिए एक योजना लेकर आए, वन

टाइम सैटलमेंट स्कीम। इस योजना में मोटा-मोटा ये है भई पिछले दो-तीन साल, चार साल जब से आपने बिल नहीं दिए उस दौरान अगर आपकी दो या दो से ज्यादा ओके रीडिंग मिलती है, ऐसी रीडिंग जो आप भी सहमत हो, जल बोर्ड भी सहमत है, दो या दो से ज्यादा ओके रीडिंग है तो उनको मान लिया जाएगा, उसकी एवरेज ले ली जाएगी और उसकी एवरेज से बाकी सारे महीनों को मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। भई आपकी एक रीडिंग आ रही है मान लो 18 हजार लीटर, एक रीडिंग है 21 हजार लीटर आप कहते हो ये दो सही है। तो 21 और 18, 39 हजार लीटर हो गई, 39 को टू से डिवाइड किया, 19. 5 हो गया, ये आपकी एवरेज रीडिंग। तो जितने महीनों का आपने बिल नहीं दिया, उतने महीनों का इसके हिसाब से मल्टीप्लाई करके आपका बिल जनरेट कर देंगे। तो उस हिसाब से एक तो ये हो गया कि भई जिस-जिस की दो या दो से ज्यादा ओके रीडिंग है, ओके रीडिंग को कैल्कुलेट। कई लोग जैसे इन्होंने बताया 2012 से किसी ने बिल ही नहीं दे रखे, मीटर ही नहीं लगा रखा, ऐसे लोग अगर अब मीटर लगाने को तैयार हो जाते हैं तो हम ये देखेंगे उसके आस-पड़ोस की, उसकी गली में रहने वालों का क्या बिल आया। क्योंकि पडोसी-पड़ोसी तो सेम कैटेगिरी के लोग है, ये भी इसका भी लीविंग स्टैंडर्ड वैसा ही है, उसका भी लिविंग स्टैंडर्ड। कच्ची कॉलोनी में रहने वालों का लिविंग स्टैंडर्ड एक जैसा है, झुग्गियों में रहने वालों का लिविंग स्टैंडर्ड एक जैसा है, रिसैटलमैंट में रहने वालों का एक जैसा है, वसंत विहार में रहने वालों का। तो हम ये देखेंगे कि उस गली के अंदर बाकी लोगों

का बिल कैसे आ रहा है। तो नेबरहुड की स्कीम इसके अंदर है, जो गली के लोगों का जिस ट्रेंड पर बिल आ रहा है, उसी हिसाब से इसका भी बिल मान लिया जाएगा। इतनी अच्छी स्कीम, इतनी शानदार स्कीम कहां हो सकती है, इतनी सही स्कीम है, इसमें भी अगर कुछ कमी है तो हम इनके साथ चर्चा करने को तैयार है, बीजेपी वाले आएं बैठे हमारे साथ चर्चा करें, कुछ चेंजिज बताएंगे हम चेंजिज कर लेंगे उसके अंदर, कोई दिक्कत नहीं है। हम तो जनता के लिए काम कर रहे हैं। तो इसमें मान लीजिए किसी का अब एवरेज आ गया 20 हजार लीटर से कम, तो 20 हजार लीटर से कम अगर हो गया तो उसके पांच-सात साल का सारा बिल माफ हो जाएगा और अगर किसी का ज्यादा आ गया तो उसका ज्यादा के हिसाब से एलपीएससी और इंट्रेस्ट माफ करके, माफ करके और हम बाकी बिल उससे ले लेंगे। हमारा अपना अंदाजा है कि इस हिसाब से लगभग साढ़े 10 लाख में से 90 प्रसैंट से ज्यादा लोगों का पानी का बिल जो है वो 20 हजार लीटर से कम आएगा और उनका सारा पुराना बिल माफ हो जाएगा, बिना एक भी पैसा दिए, बिना एक भी पैसा दिए उनके दफ्तरों के चक्कर बंद हो जाएंगे और वो अपना सुख-शांति से जीना शुरू कर देंगे। दूसरी तरफ जल बोर्ड दुखी हो रहा है क्योंकि जल बोर्ड के साढ़े 10 लाख कंज्यूमर बिल नहीं दे रहे। वो हर बार ग़र्जी बिल रेज कर रहे हैं, हर बार अपने खातों में दिखा रहे हैं, जल बोर्ड का रेवेन्यू फंसा हुआ है, जल बोर्ड का अगर बीस हजार, जितने 90 प्रसैंट लोगों के बिल माफ होंगे, जल बोर्ड को उतना पैसा दिल्ली सरकार से मिल जाएगा। क्योंकि दिल्ली

सरकार रिइम्बर्स करती है सारी सबसिडी। तो जल बोर्ड का रेवेन्यू आ जाएगा, जल बोर्ड का रेवेन्यू हजारों करोड़ रुपया आज लॉक हो गया है इसके अंदर। इतनी अच्छी स्कीम है, ये जैसा इन्होंने बताया 13 जून पिछले साल 2023 को इस स्कीम को पास किया गया था और इसे तो तुरंत लागू कर देना चाहिए था। आठ महीने हो गए आज, 8 महीने हो गए हमें इन अफसरों के और इनके वो करते-करते लेकिन इन्होंने करने से मना कर दिया। आज स्थिति ये है कि इस स्कीम को कैबिनेट में लाना है, कैबिनेट पास करेगी तब ये स्कीम लागू होगी, इसके लिए पफाइनेंस सेक्रेटरी को इसपर अपने कमेंटस देने है, पफाइनेंस सेक्रेटरी ने फाइल पर लिख दिया मैं कमेंटस नहीं देता। सोचो किसी अफसर की हिम्मत है। उसने फाइल पर लिख दिया पफाइनेंस सेक्रेटरी ने कि मैं कमेंटस नहीं देता, बिधूड़ी जी कह रहे थे मेरे से सीख लो, जरा सिखाओं अब उसका क्या करें हम।

...व्यवधान...

माननीय मुख्यमंत्री: मैं बाद में मिल लूंगा, चाय पर आना, चाय पर बता देना कि फाइनेंस सेक्रेटरी ने फाइल पर लिख दिया मैं कमेंटस नहीं देता। सौरभ भारद्वाज जी यूडी मिनिस्टर हैं, इन्होंने यूडी सेक्रेटरी को लिखित आदेश दिया की इसको प्रस्ताव को कैबिनेट में लाया जाए। यूडी सेक्रेटरी ने फाइल पर लिख दिया मैं इसको कैबिनेट में नहीं लाता, जब तक फाइनेंस सेक्रेटरी कमेंटस नहीं देगा। फाइनेंस सेक्रेटरी कह रहा है मैं कमेंटस नहीं दूंगा, यूडी सेक्रेटरी कह रहा है जब तक ये कमेंटस नहीं देगा मैं। तो हमने इन दोनों को और और भी अफसरों को बुलाया इन

मंत्रियों ने। इन्होंने मेरे को बताया मंत्रियों ने कि ये क्या चल रहा है, क्यों कर रहे हो ऐसा। तो अध्यक्ष महोदय आपको जान के ताज्जुब होगा कि एक-दो सीनियर, सीनियर मोस्ट आईएएस ऑफिसर प्रिंसिपल सेक्रेटरी लेवल के, फूट-फूट के रोने लग गए, आँसू बह रहे थे उनकी आंखो से। ये उम्र रोने की नहीं है, एक आईएएस अफसर को इस तरह से मैंने रोते हुए नहीं देखा, फूट-फूट के रोने लग गए, बोले जी हमारी नौकरी का सवाल है। हमें धमकी दी जा रही है। हमने कहा कौन दे रहा है, कहता है हायर अपस, हायर अपस का क्या मतलब है आप लोग सोच सकते हो। ऊंचे से हमको धमकी दी जा रही है कि अगर तुमने ये स्कीम पास कर दी दिल्ली वालों के लिए तो तुमको सस्पेंड कर देंगे। अगर तुमने ये स्कीम पास कर दी, इसीलिए ये इतना लड़ रहे हैं, ये सर्विसिसज, सर्विसिसज करते रहते हैं, क्यों करते रहते हैं ये? नीयत खराब है इन लोगों की। सर्विसिसज चाहिए, सर्विसिसज इसीलिए उनको धमकी दी जा रही है कि तुम्हें सस्पेंड कर देंगे, तुम्हें नौकरी से निकाल देंगे, तुम्हारे को जेल भेज देंगे, ईडी, सीबीआई छोड़ देंगे तुम्हारे पीछे। वो बोले जी आप हमें, सर आप कहो तो इस्तीफा दे देंगे हम हम नौकरी से लेकिन ये स्कीम हम पास नहीं कर सकते। एक तरह से दिल्ली के अंदर एक सीरियस कन्स्टीट्यूशनल क्राइसिस पैदा हो गया है जिसके अंदर ओफिसर्स ने लिखकर दे दिया है कि हम काम नहीं करेंगे। अगर वो काम नहीं करेंगे, ऑफिसर्स लिखकर दे रहे हैं कि काम नहीं करेंगे, सरकार कैसे चलेगी? क्या सरकार दो दिन भी चल सकती है, क्या ये शोभा देता है केंद्र सरकार को, बीजेपी को ये शोभा देता है?

इस स्थिति के अंदर उन्होंने दिल्ली की चुनी हुई सरकार को लाके खड़ा कर दिया है। और इस सारे के पीछे कौन है, इस सबके पीछे बीजेपी है। बीजेपी दिल्ली वालों से नफरत करती है, नफरत करती है। दिल्ली वाले दुखी होते हैं, बीजेपी में खुशी की लहर दौड़ जाती है। दिल्ली वाले बीमार होते हैं, बीजेपी वाले आनंदित होते हैं। दिल्ली को बर्बाद करना चाहते हैं बीजेपी के लोग। जैसा परसों मैंने बताया था किस तरह से इन्होंने दो महीने के लिए दिल्ली के अस्पतालों की दवाईयॉं बंद कर दी। किस तरह से इन्होंने दो महीने के लिए पिछली बार मोहल्ला क्लीनिक के तीन महीने के लिए रैंट नहीं पे किए, मोहल्ला क्लीनिक कई किराए पर चल रहे हैं, उनके रेंट नहीं दिए, उनके बिजली के बिल नहीं दिए इन्होंने, डॉक्टरों की तनखा नहीं दी इन्होंने, एमटीएस कर्मचारियों को निकाल दिया इन लोगों ने, योगा क्लासिसिज दिल्ली के अंदर बंद कर दी इन्होंने। दिल्ली वालों से इतनी नरत करते हैं ये लोग और मैं दिल्ली वालों को कहना चाहता हूं जबतक आपका बेटा जिंदा है, इन बीजेपी वालों के सामने दीवार बनकर खड़ा है, बाल-बांका नहीं होने दूंगा। और अब ये इस स्कीम का विरोध कर रहे हैं। मुझे बेहद खुशी है अभी-अभी इन्होंने बिधूड़ी साहब ने कहा कि हम स्कीम का विरोध नहीं कर रहे। अगर आप स्कीम का विरोध नहीं करते फिर तो राजनीति एक तरफ है, आपसे मेरा निवेदन है, आप ही के एल. जी. हैं, आप ही की पार्टी के हैं। आप एक बारी सारे जाकर, आप सारा क्रैडिट आपका मैं लाल किले के ऊपर खड़ा होकर चिल्लाऊंगा जोर-जोर से कि बीजेपी वालों ने कराया, वोट बीजेपी वालों को दे देना, मैं बोलूंगा कि

बीजेपी वालों ने कराया। वोट के लिए ही कर रहे हो और तो कोई कारण नहीं है, वोट आप ले लो सारे, हमें नहीं चाहिए वोट, हमें तो सेवा करने का मौका मिला है यही भगवान ने कोई पुराने जन्म में पुण्य किए होंगे हम लोगों ने जो हमें ये मौका दे दिया भगवान ने। ये सारी चीजें लेकर मैं एल.जी. साहब के पास गया। मैंने एल.जी. साहब को बताया, मैंने कहा एल.जी.साहब ये धमकी दी जा रही है अफसरों को, उनको कहा जा रहा है कि खबरदार अगर तुमने ये स्कीम पास कर दी तो तुमको बख्शेंगे नहीं। तो एल.जी. साहब ने कहा कि उनको इसके बारे में जानकारी नहीं है और उनका इससे कोई लेना-देना नहीं है, उनको इसके बारे में पता नहीं है। तो आज मैं इस सदन के माध्यम से एल.जी. साहब से हाथ जोड़कर विनती करना चाहता हूं कि एल.जी. साहब एक बार अगर आप फोन भी कर देंगे उठा के इन अफसरों को कि भई ये स्कीम पास करनी है, शाम तक स्कीम पास हो जाएगी इतना ही है बस, तीन घंटे में स्कीम पास हो जाएगी, तीन घंटे का है। मेरा एल.जी. साहब से निवेदन है हाथ जोड़ के, सारे सदन की तरफ से, इस पूरे सदन की तरफ से मेरा निवेदन है एल.जी. साहब इस स्कीम को आप अफसरों को फोन कर दो और वो कर दें और अगर आपके फोन के बावजूद नहीं करें, तो एल.जी. साहब के पास पावर है इनको सस्पेंड करने की, हमारे पास तो नहीं है। तो इन अफसरों को तुरंत सस्पैंड किया जाए और उनको नौकरी से बाहर किया जाए, अगर उसके बावजूद भी ये लोग ना करें। यहां जितने आप लोग बैठे हैं मेरा आप सब लोगों से निवेदन है जितने एमएलएज बैठे हैं इन साढ़े दस

लाख परिवारों के घर-घर जाना, एक-एक के घर जाना आप लोग और घर-घर जाकर जनता से कहना कि आपका बिल गलत आया है, जी वो कहेगा हाँ जी आया है, बोलो जी ये बीजेपी वाले करा रहे हैं पर चिंता मत करो आपका बेटा लगा हुआ है, आपका बेटा आपका बिल ठीक कराकर छोड़ेगा। जब तक ठीक नहीं हो जाता बिल भरने की जरूरत नहीं है, हम आपके साथ हैं। कोई बिल भरने की जरूरत नहीं है, कोई चक्कर काटने की जरूरत नहीं है, जल बोर्ड के चक्कर काटना बंद कर दो, केजरीवाल आपका बेटा है आपके साथ है, घर-घर जाना और घर-घर जाकर इसको करा कर आना। और अगर इन्होंने नहीं किया, बिधूड़ी साहब हमारे पास कोई चारा नहीं रहेगा, दिल्ली में बहुत बड़ा आंदोलन होगा इसके बारे में। हमें आंदोलन तो करना आता है, आंदोलन से ही निकले हुए लोग हैं, फिर दिल्ली में आंदोलन होगा, करना तो पड़ेगा। सीधी उंगली से कर दो नहीं तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी। ये जनता करेगी हम नहीं करेंगे। अभी बिधूड़ी साहब ने कहा कि जनता को ये पसंद नहीं है कि हम कहते हैं काम नहीं करने दे रहे, काम नहीं करने दे रहे, जनता जानती है ये गंदे लोग काम नहीं करने दे रहे, लेकिन केजरीवाल उनका बेटा फिर भी सारे काम करा लेता है। आपने मोहल्ला क्लीनिक रोके, रूकने दिए हमने? आपने सीसीटीवी कैमरे रोके, एल.जी. के घर उनके वेटिंग रूम के अंदर 10 दिन तक दिल्ली का मुख्यमंत्री वहां पर धरना, उसके कमरे के अंदर धरना देकर आया था सीसीटीवी कैमरे तब पास हुए थे। आपने पिछले साल दवाईयाँ रोकी, हमने फिर चालू कराई, आपने फरिश्ते स्कीम रोकी हम सुप्रीम कोर्ट गए

और सुप्रीम कोर्ट से फरिश्ते स्कीम पास कराकर लाए। आपने जल बोर्ड का पैसा रोका, 6 महीने आपने जल बोर्ड का पैसा रोका, हाईकोर्ट से ऑर्डर कराकर ले आए जल बोर्ड का पैसा मिलेगा। आप काम रोकते रहो, हम काम कराते रहेंगे। डीटीसी पेंशन आपने रोकी हमने डीटीसी पेंशन भी दिलवा दी सबकी। किसी को मारने वाले से उसकी जान बचाने वाला ज्यादा बड़ा होता है। तो मैं आज इस हाउस के माध्यम से दो चीजों की, एक तो एल.जी. साहब से निवेदन करना चाहता हूं हाथ जोड़कर पूरी विनती के साथ और दूसरा मैं बीजेपी को जिम्मेदारी देना चाहता हूं अगर सारा हाउस इसके लिए मंजूर है कि बीजेपी इसकी जिम्मेदारी ले की वो एल.जी. साहब से कहकर इस स्कीम को पास कराकर लाए क्योंकि आप भी कह रहे हो कि ये स्कीम अच्छी है, पूरे हाउस का इसपर सहमति है कि ये स्कीम अच्छी है, होनी चाहिए। साढ़े दस लाख परिवारों को इसका फायदा मिलेगा, तो आप इसकी जिम्मेदारी लेकर इसको कराकर लाइये, बहुत–बहुत शुक्रिया मैं इसका समर्थन करता हूं।

माननीय अध्यक्षः अब श्री राजेंद्र पाल गौतम माननीय सदस्य द्वारा प्रस्तुत संकल्प सदन के सामने है, जो इसके पक्ष में है वो हाथ खड़ा करें।

माननीय अध्यक्षः धन्यवाद, धन्यवाद। जो इसके विरोध में है, कोई नहीं।

(सदस्यों के हाथ खड़ा करने पर)

हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता संकल्प सर्वसम्मति से पारित हुआ।

अब सदन की कार्यवाही मंगलवार, दिनांक 20 फरवरी, 2024 को पूर्वाह्न 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। लंच तैयार है, माननीय सदस्य लंच लेकर जाएंगे।

(सदन की कार्यवाही दिनांक 20 फरवरी, 2024 को
पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई।)

© दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन अधिनियम, 1991 की धारा 18 (2) के उपबंधों तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली विधान सभा प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 281 (2) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रकाशित तथा ग्राफिक प्रिंटर्स, 2965 /41, बीडनपुरा, करोल बाग, नई दिल्ली-110 005 द्वारा मुद्रित।